सांध्य दैनिक

श्रीकंचनपथ

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534
डाक पंजीयन क्र.-छ.ग./दुर्ग/1000000029/2026-28

वर्ष- 17 अंक - 184 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, शनिवार 18 अप्रैल 2026 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

खास-खबर

छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का कहर, 44 डिग्री तक पहुंचा पारा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में गर्मी का असर अब चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में दिनभर तेज धूप और गर्म हवा चल रही है। मौसम विभाग ने बताया कि फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं है और अगले दो दिनों तक इसी तरह के हालात बने रह सकते हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, उत्तर भारत से लेकर छत्तीसगढ़ तक फैली द्रोणिका, ओडिशा के पास सक्रिय चक्रवातीय परिसंचरण और महाराष्ट्र-तेलंगाना क्षेत्र में बने एंटी साइक्लोन के कारण गर्म हवाओं का प्रवाह लगातार बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा तापमान राजनांदगांव में 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के कई हिस्सों में लू जैसे हालात बनने की चेतावनी जारी की गई है। राजधानी रायपुर में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

पुणे में एयरफोर्स के विमान की हार्ड लैंडिंग, 8 घंटे बंद रहा रनवे

पुणे। पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुक्रवार रात भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान की हार्ड लैंडिंग हुई। रात 10:30 बजे हुई इस घटना के बाद रनवे को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। जिसके कारण एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन 8 घंटे तक प्रभावित रहा। आईएएफने खुद इसकी जानकारी दी और कहा विमान का क्रू सुरक्षित है। एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन सुबह 7.30 बजे के बाद नॉर्मल हो सका। एयरपोर्ट डायरेक्टर के मुताबिक, रनवे के मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया है। दिन भर में ऑपरेशन सामान्य हो जाएगा।एयरपोर्ट डायरेक्टर के मुताबिक 5 एयरलाइंस की 91 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी थीं। इनमें इंडिगो की 65, एअर इंडिया की 6, स्पाइसजेट की 5, अकासा एयर की 5, एअर इंडिया एक्सप्रेस की 10 फ्लाइट्स शामिल थीं।

संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, नहीं पास हो सका संविधान संशोधन विधेयक

नईदिल्ली। लोकसभा में सीटें बढ़ाने के लिए लाया गया संविधान का 131वां संशोधन बिल सरकार लोकसभा में पास नहीं करा पाई। इसमें संसद की 543 सीटें बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान था। लोकसभा में बिल पर 21 घंटे की चर्चा के बाद वोटिंग हुई। उपस्थित 528 सांसदों ने वोट डाले। पक्ष में 298, विपक्ष में 230 वोट पड़े। बिल पास कराने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत थी। 528 का दो तिहाई 352 होता है। इस तरह बिल 54 वोट से गिर गया। अब महिला आरक्षण नई जनगणना के नतीजे आने से पहले लागू नहीं होगा, यानी 2029 के लोकसभा चुनाव में इसका फायदा नहीं मिलेगा। इसके साथ लोकसभा व राज्यसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है।

सरकार ने लोकसभा में तीन बिल पेश किए थे। इसमें संविधान (131वां) संशोधन बिल, परिसीमन संशोधन संविधान बिल 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल 2026 शामिल थे। महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। हालांकि यह अब 2034 तक लागू होगा। इसके लिए परिसीमन की जरूरत है। परिसीमन का मतलब है कि देश की आबादी के आधार पर लोकसभा और विधानसभा की सीटों की सीमाएं और संख्या तय करना। यह काम एक परिसीमन आयोग करता है। पहले तय होगा कि किस राज्य में कितनी सीटें होंगी। किन इलाकों की सीमाएं क्या होंगी। उसके बाद ही आरक्षण तय हो पाएगा।

रूसी तेल पर भारत को मिली बड़ी खुशखबरी अमेरिकी सरकार ने बढ़ाई एक माह की छूट

- इनकार के बाद अमेरिका का यू-टर्न, रूस ने भारत को बताया बेहतर साझेदार

नई दिल्ली। अमेरिका ने भारत और दूसरे देशों को रूस से तेल और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए दी गई छूट को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। ईरान युद्ध के कारण दुनिया में तेल की सप्लाई बाधित हुई थी। इसके देखते हुए अमेरिका ने भारत और कई अन्य देशों को रूस से तेल खरीदने की अनुमति दी थी। लेकिन इसकी मियाद पिछले शनिवार को खत्म हो गई थी। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने हाल में कहा था कि अमेरिका रूसी और ईरानी तेल पर दी गई छूट को रिन्यू नहीं करेगा।

भारत के लिए अमेरिका ने रूसी तेल खरीद पर लगी छूट को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने देर रात नया लाइसेंस जारी कर बताया कि अब देशों को 16 मई तक समुद्री मार्ग से रूसी तेल को खरीदने की अनुमति होगी। इससे पहले यह छूट 11 अप्रैल को समाप्त हो चुकी थी। हालांकि, इस लाइसेंस में ईरान, क्यूबा और उत्तर कोरिया से संबंधित किसी भी लेन-देन को शामिल नहीं किया गया है। इस फैसले से भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने में आसानी होगी। भारत पहले ही रूस से बड़े पैमाने पर तेल आयात कर रहा है।

भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने भरोसा दिलाया है कि रूस भारत को कच्चा तेल, एलपीजी और एलएनजी की सप्लाई और बढ़ाएगा। उन्होंने भारत को एक विश्वसनीय साझेदार बताया।

सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार, मार्च में भारत ने रूस से 5.8 अरब डॉलर का कच्चा तेल खरीदा, जो फरवरी के 1.54 अरब डॉलर की तुलना में तीन गुना से अधिक है। मार्च 2022 के बाद से, नई दिल्ली रूसी तेल के लिए एक प्रमुख बाजार के रूप में उभरी है। 2024 में, भारत ने रूस से प्रतिदिन लगभग 20 लाख बैरल तेल खरीदा, जबकि पिछले साल यह आयात लगभग 44 अरब डॉलर का था।

भारत में रूसी तेल की सप्लाई

2024 में भारत ने रूस से रोजाना औसतन 2 मिलियन बैरल कच्चे तेल की खरीद की। पिछले साल भी भारत ने रूस से करीब 44 अरब डॉलर का कच्चा तेल खरीदा था। अमेरिका के दबाव के कारण भारत ने पिछले साल के आखिरी महीने में रूस से तेल की खरीदारी में कटौती की थी लेकिन इसके बावजूद रूस सबसे बड़ा सप्लायर बना रहा। होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही बंद होने के कारण दुनिया में तेल और गैस का संकट खड़ा हो गया था। इस कारण अमेरिका ने भारत और दूसरे देशों को रूसी तेल खरीदने की अनुमति दी थी।

बड़ा हादसा : तीन ट्रेलर और एक कार में टक्कर, चार लोग घायल

श्रीकंचनपथ न्यूज

कोरबा। राष्ट्रीय राजमार्ग-130 कोरबा-कठघोरा मार्ग पर शनिवार अलसुबह करीब 6 बजे एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें तीन ट्रेलर और एक कार आपस में टकरा गईं। हादसे में चार लोग घायल हुए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के अनुसार, बांगो थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गुरसिया-जड़गा मोड़ के पास अंबिकापुर की ओर से आ रहे दो ट्रेलर आपस में टकरा गए। टक्कर इतनी तेज थी कि एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर सामने से आ रही कार से जोरदार भिड़ गया। टक्कर के प्रभाव से कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इसी दौरान पीछे से आ रहा एक और ट्रेलर नियंत्रण खो बैठा और सड़क पर पलट गया।

सूचना मिलते ही बांगो थाना पुलिस टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को नजदीकी अस्पताल भेजा, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। प्रशासन ने क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन की मदद से सड़क किनारे हटवाकर यातायात बहाल करने का काम शुरू किया। हादसे के कारण राजमार्ग पर कुछ देर तक लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने यातायात को डायवर्ट कर सुचारु किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मोड़ पर भारी वाहनों की रफ्तार और ओवरटेकिंग अक्सर हादसों का कारण बनती है।

छत्तीसगढ़ प्लांट हादसे में अब तक 22 की मौत

- बंगाल के मजदूर ने तोड़ा दम, 14 का इलाज जारी

सक्ती। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में हुए वेदांता प्लांट हादसे में घायल 1 और मजदूर ने दम तोड़ दिया है। बंगाल के मजदूर सुब्रोतो जेना (80-90% झुलसे) की रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान शनिवार सुबह मौत हो गई। मौत का आंकड़ा बढ़कर 22 पहुंच गया है।

इससे पहले मध्यप्रदेश के रहने वाले किस्मत अली ने रायपुर के निजी अस्पताल में दम तोड़ा था। हादसे में कुल 36 लोग झुलसे हैं, 14 घायलों का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज जारी है।

घटना के बाद वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल, प्रबंधन समेत 10 लोगों के खिलाफ डभरा थाने में स्त्रद्धक्रदर्ज हुई है। घटना के 24 घंटे बाद औद्योगिक सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हादसे की जांच की थी। जिसमें प्लांट प्रबंधन की गंभीर लापरवाही सामने आई है।

शुरुआती जांच के मुताबिक, प्रोडक्शन दोगुना करने की जल्दबाजी में बॉयलर फटा। चेतावनी के बाद भी काम नहीं रोका गया। इसके अलावा मशीनों के रखरखाव और संचालन में लापरवाही बरती गई। इसी आधार पर केस दर्ज किया गया है।

अग्निवीर के अभ्यर्थियों को रायपुर में मिलेगी फ्री कोचिंग

- चार मई से 4 जून तक एक माह तक चलेगा प्रशिक्षण

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 4 मई से 4 जून 2026 तक संचालित होगा।

इस कोचिंग का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा, जिन्होंने 13 फरवरी से 10 अप्रैल के बीच अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन किया था। इच्छुक उम्मीदवारों को इस प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदन की प्रक्रिया रोजगार विभाग के आधिकारिक पोर्टल या मोबाइल एप के माध्यम से पूरी की जा सकती है। प्रशिक्षण की व्यवस्था जिला और विकासखंड स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में की जाएगी। प्रशिक्षण का उद्देश्य अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए बेहतर तरीके से तैयार करना है, ताकि वे भर्ती प्रक्रिया में सफल हो सकें। किसी भी प्रकार की जानकारी या समस्या के समाधान के लिए अभ्यर्थी रोजगार कार्यालय रायपुर से संपर्क कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कानून पर बवाल, हाईकोर्ट पहुंचा ईसाई समुदाय

श्रीकंचनपथ न्यूज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक और अधिनियम लाया है। इस विधेयक में दिए गए प्रावधानों का ईसाई समाज विरोध कर रहा है और बिलासपुर हाई कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में ईसाई समाज ने कहा है, अवैध धर्मांतरण पर आजीवन कारावास की सजा गलत है। ईसाई समाज के प्रतिनिधि क्रिस्टोफर पॉल ने संबंधित विधेयक के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

याचिकाकर्ता क्रिस्टोफर पॉल ने अपनी याचिका में कहा कि यह कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मिले धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। याचिका में कहा गया कि इस कानून में अवैध धर्मांतरण पर आजीवन कारावास जैसी सजा देना असंवैधानिक है। क्रिस्टोफर पॉल ने इस विधेयक के कई कड़े प्रावधानों को असंवैधानिक बताते हुए विधेयक को रद्द करने की मांग की है। क्रिस्टोफर पॉल की याचिका के मुताबिक इस विधेयक की परिभाषाएं साफनहीं हैं, जिससे मनमानी कार्रवाई की आशंका बढ़ गई है। यह विधेयक व्यक्तिगत निजता और आस्था के अधिकार में हस्तक्षेप करता है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है, इस विधेयक को राज्य सरकार टारगेट कर हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। मसीही समाज की तरफ से आरोप लगाया गया है, इस कानून का इस्तेमाल उत्पीड़न के लिए हो सकता है।

गजेन्द्र यादव ने कहा- गलत काम करने वालों की घबराहट

इस पूरे मामले पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस कानून के खिलाफविरोध कर रहे हैं या अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं, वे खुद अपने कृत्यों पर संदेह जता रहे हैं। उनके मुताबिक, अगर सब कुछ सही होता तो इस तरह की प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं पड़ती। छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि यह कानून जबरन, लालच या धोखे से किए जाने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए बनाया गया है। नए प्रावधानों के तहत ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।

शिक्षकों ने किया जनगणना की ड्यूटी का विरोध

- गर्मी की छुट्टियों में ड्यूटी लगाने से नाराज शिक्षक

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। 1 मई से शुरू होने जा रही जनगणना में शिक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने का विरोध तेज हो गया है। गर्मी की छुट्टियों के दौरान ड्यूटी लगाने से नाराज शिक्षकों ने इसे अव्यवहारिक बताया है। शिक्षकों का कहना है कि मई-जून में भीषण गर्मी पड़ती है, ऐसे में घर-घर जाकर सर्वे करना बेहद कठिन होगा। उन्होंने कहा कि एक तरफ छुट्टियों में स्कूल बंद रहते हैं, वहीं दूसरी ओर इसी समय उन्हें फील्ड में काम करने के लिए भेजा जा रहा है।

छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने बताया कि मौसम की परिस्थितियों को नजरअंदाज कर यह निर्णय लिया गया है। इतनी गर्मी में लंबे समय तक बाहर रहकर डोर-टू-डोर सर्वे करना न सिर्फ मुश्किल है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी जोखिम भरा है। शिक्षक संघ ने मांग की है कि जनगणना ड्यूटी के समय और प्रक्रिया पर पुनर्विचार किया जाए, ताकि शिक्षकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। इन सबके साथ ही स्मार्ट फोन को लेकर भी शिक्षकों को शिकायत है, जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों के पास एंड्रॉयड मोबाइल में कम से कम 12.0 वर्जन का सॉफ्टवेयर होना अनिवार्य किया गया है। ऐसे में जिन कर्मचारियों के पास पुराने मोबाइल हैं, उन्हें अब नया स्मार्टफोन लेना होगा।

पश्चिम एशिया में फिर शुरू होगी जंग! 14 दिन के युद्धविराम पर ट्रंप का बड़ा बयान

वाशिंगटन। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे संघर्ष विराम को लेकर बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा सीजफायर को आगे बढ़ाया भी जा सकता है और नहीं भी, यह पूरी तरह हालात पर निर्भर करेगा।

एयर फोर्स वन विमान में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि अगर तय समय तक कोई समझौता नहीं होता है, तो सीजफायर को आगे बढ़ाने की संभावना कम हो सकती है। उनका यह बयान क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका को और मजबूत करता है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की नौसैनिक नाकाबंदी जारी रहेगी, लेकिन युद्ध विराम की स्थिति पर अंतिम फैसला बातचीत के नतीजों पर निर्भर करेगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि हालात बिगड़ने पर सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू हो सकती है। ट्रंप ने कहा 'शायद मैं इसे आगे न बढ़ाऊं, लेकिन नाकाबंदी जारी रहेगी। अगर समझौता नहीं हुआ तो हमें फिर से कार्रवाई करनी पड़ सकती है।

22 अप्रैल को सीजफायर होगा खत्म

गौरतलब है कि मौजूदा सीजफायर 22 अप्रैल को समाप्त होने वाला है और इसी को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की एक नई कोशिश भी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल सोमवार को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मुलाकात कर सकते हैं। इस बातचीत का उद्देश्य लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करने के लिए एक नया रास्ता निकालना है। इससे पहले 11 से 12 अप्रैल के बीच इस्लामाबाद में हुई वार्ता को ऐतिहासिक तो माना गया, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका था। इस बातचीत की मध्यस्थता पाकिस्तान ने की थी और यह 1979 की ईरानी क्रांति के बाद पहली सीधी उच्च स्तरीय वार्ता थी।

संपादकीय

संविधान संशोधन बिल ध्वस्त

महिला आरक्षण व परिसीमन विधेयक सिरे न चढ़े

जैसे कि पहले से कायस लगाए जा रहे थे, शुक्रवार को लोकसभा में संविधान में प्रस्तावित 131वां संशोधन बिल मतदान के बाद गिर गया। दरअसल, यह बिल देश में महिला आरक्षण कानून में संशोधन के लिए लाया गया था। राजनीतिक पंडित पहले ही कह रहे थे कि संविधान संशोधन के लिये जरूरी दो तिहाई बहुमत सरकार के पास नहीं है, जिससे बिल के पारित होने पर संशय था। वैसा ही हुआ और राजग सरकार दो तिहाई वोट हासिल करने में विफल रही। बिल के समर्थन में 298 और इसके विरोध में 230 वोट पड़े। आखिरकार सरकार की ओर से कहा गया कि अब दोनों बाकी प्रस्तावित संशोधन बिलों को आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि महिलाओं को 33 आरक्षण देने वाले कानून में संशोधन को लेकर बुलाए गए विशेष सत्र में पिछले कुछ दिनों से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गरमागरम बहस जारी थी। विपक्ष इस संशोधन में शामिल परिसीमन को लेकर सरकार की घेराबंदी कर रहा था। दरअसल, दक्षिण भारत के उन राज्यों में इसको लेकर खासा विरोध था जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण करके आर्थिक विकास को प्राथमिकता बनाया था। उनकी आशंका थी कि परिसीमन विधेयक के अस्तित्व में आने से संसद में इन राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। विपक्ष में का आरोप है कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण संशोधन बिल को पारित करने का उपक्रम महज कुछ राज्यों में हो रहे चुनाव में बढ़त हासिल करने के लिये था। ताकि महिला वोटरों को लुभाया जा सके। विपक्ष ने संसद में जारी बहस के बीच कानून मंत्रालय द्वारा महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को लागू करने के लिये अधिसूचना जारी करने पर भी सवाल उठाये। उल्लेखनीय है कि महिला आरक्षण कानून का उद्देश्य संसद और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिये 33 फीसदी आरक्षण लागू करने का प्रावधान था। मगर राजग सरकार ने प्रस्तावित 131वें संविधान बिल 2026 में सीटों में आरक्षण को परिसीमन के आधार पर लागू करने की बात कही थी।

> "उल्लेखनीय है कि महिलाओं को 33 आरक्षण देने वाले कानून में संशोधन को लेकर बुलाए गए विशेष सत्र में पिछले कुछ दिनों से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गरमागरम बहस जारी थी। विपक्ष इस संशोधन में शामिल परिसीमन को लेकर सरकार की घेराबंदी कर रहा था। दरअसल, दक्षिण भारत के उन राज्यों में इसको लेकर खासा विरोध था जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण करके आर्थिक विकास को प्राथमिकता बनाया था। उनकी आशंका थी कि परिसीमन विधेयक के अस्तित्व में आने से संसद में इन राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। विपक्ष में का आरोप है कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण संशोधन बिल को पारित करने का उपक्रम महज कुछ राज्यों में हो रहे चुनाव में बढ़त हासिल करने के लिये था।

दरअसल, विपक्ष इस संशोधन बिल की टाइमिंग और आरक्षण को परिसीमन के आधार पर लागू करने की शर्त पर सवाल उठाता रहा है। कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया कि 33 फीसदी आरक्षण को लोकसभा की मौजूदा सीटों के आधार पर ही लागू करना चाहिए। विपक्ष परिसीमन से उपजी विसंगतियों और दक्षिण के राज्यों की चिंताओं को तरजीह देने की बात करता रहा है। वहीं सत्ता पक्ष की दलील रही कि विपक्ष महिला आरक्षण का विरोध कर रहा है। बिल का मकसद महिला सशक्तीकरण ही है। जिसके लिये इसके लागू करने के तरीके का विरोध किया जा रहा है। सत्ता पक्ष की दलील थी कि परिसीमन संविधान सम्मत है और बढ़ती आबादी के बाद सीटों को तार्किक बनाये जाने की जरूरत है। इस बीच दोनों पक्षों की ओर से एससी-एसटी के हितों के पैरोकार होने की दलीलें भी दी गई। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर उत्तर-दक्षिण का नैरेटिव गढ़ने का आरोप भी लगाया। साथ ही विपक्ष को महिलाओं के आक्रोश की कीमत चुकाने की भी चेतावनी दी। वहीं विपक्ष ने केंद्र पर देश का चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि ये संशोधन दलित व पिछड़े वर्गों के हित में नहीं है। सवाल इस बात को लेकर भी उठाये गए कि 2011 की जनगणना को आधार बनाकर परिसीमन करना कितना न्यायसंगत है। इसके लिये नये जनगणना के आंकड़े आने का इंतजार क्यों नहीं किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने परिसीमन को संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाला बताया। उन्होंने महिला आरक्षण लागू करने को परिसीमन से जोड़ने की तार्किकता को लेकर भी सवाल उठाया। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को खारिज किया कि निर्णय प्रक्रिया किसी भी तरह किसी के साथ भेदभाव करेगी। उन्होंने कहा कि परिसीमन पहले के अनुपात के अनुसार ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 33 फीसदी महिलाओं को यहां आने दें और उन्हें निर्णय करने दें।

उगते सागर ने बचपन छीन बढ़ाये बाल विवाह

अमरेन्द्र किशोर

सुंदरबन जैसे इलाके में बड़ी संख्या में किशोरियों की शादी मात्र 'परंपरा' नहीं। यह कमजोर आर्थिक हालत में जीवन-रक्षा की रणनीति है। समुद्र में बार-बार चक्रवात आने, तटबंध टूटने, खारी मिट्टी से कृषि व मछली पालन प्रभावित होता है, जिससे आजीविका पर संकट आने से बाल-विवाह बढ़ते हैं।

सुंदरबन इलाके में जब सागर की लहरें धीरे-धीरे दलदली मिट्टी पर आती हैं- नमक और तूफान की तीव्रता से बंधा तट कांपता है, वहां बचपन की मासूमियत भी खतरे में पड़ जाती है। यहां गांवों में, घर की दीवारें धंसती मिट्टी पर टिकी हैं। इस संकट में सबसे अधिक प्रभावित होती हैं लड़कियां, जिनकी उम्र के सबसे खूबसूरत पल यानी खेल, पढ़ाई और बचपन की जिज्ञासाओं से लबालब होते हैं। वे सब जलवायु आपदाओं, गरीबी और सामाजिक असमानताओं के दबाव में जल्दी ही विवाह की आग में झोंक दी जाती हैं।

गोसाबा द्वीप की गलियों में एक 14 वर्षीय लड़की, अजूं बागदीस, सुबह के अंधेरे में अपने छोटे-छोटे पैरों से खारे पानी में छलकते पानी को चीरते हुए भागती है, अपने साथ केवल कुछ कपड़ों का बंडल लिए हुए। सूरज की पहली किरणों से पहले ही वह अपनी जीवन यात्रा में उस मोड़ पर पहुंच चुकी होगी, जहां उसके बचपन को हमेशा के लिए त्याग दिया जाएगा। विवाह की रस्में साधारण होती हैं—कोई भव्य दावत नहीं, बस कुछ रिश्तेदार, उधार ली गई साड़ी और एक जीवन जिसे आज़ाद महसूस करने का मौका कभी नहीं मिलेगा। यह जलवायु संकट की अदृश्य कीमत है, जिसे समाज और व्यवस्था ने लड़कियों की मासूमियत के रूप में वसूल लिया।

हालिया सर्वेक्षण इस संकट की गंभीरता को उजागर करते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 में पाया गया कि पश्चिम बंगाल में 20-24 वर्ष की उम्र की लगभग 42 प्रतिशत महिलाएं 18 वर्ष की उम्र से पहले ही विवाहिता हो चुकी थीं, जो राष्ट्रीय औसत 23.3 प्रतिशत का लगभग दोगुना है। सुंदरबन के द्वीपों में, गोसाबा ब्लॉक खासकर बाल विवाह के लिए चिन्हित है, जहां किशोरियों को घर का बोझ घटाने को विवाह करने को मजबूर किया जाता है। यहां के ग्रामीण रात में किए जाने वाले विवाहों की कहानियां फुसफुसाते हैं, जो अक्सर बिना पंजीकरण, अधिकारी की नज़र से दूर, अनदेखी रह जाती हैं। यूनिसेफ के अनुमान के अनुसार, भारत के बाल विवाहों में पश्चिम बंगाल की हिस्सेदारी 13-15 प्रतिशत है, और इस

डेल्टा के द्वीप-गोसाबा से लेकर बसंती, काकद्वीप और नामखाना तक—हर साल सैकड़ों किशोरियों को विवाह के बंधन में बांधते हैं।

सरकारी हस्तक्षेप मौजूद हैं, लेकिन वे सतह तक ही सीमित हैं। साल 2023 में अधिकारियों ने दावा किया कि 1,500 बाल विवाहों को रोका गया और लगभग 900 एफआईआर दर्ज की गईं, लेकिन कार्यकर्ताओं का कहना है कि अधिकांश विवाह अब भी रिकॉर्ड में नहीं आते। इस क्षेत्र में बाल विवाह भूख, कर्ज व अनिश्चितता से निपटने की कठोर रणनीति है।

जलवायु परिवर्तन इस चक्र को और तेज करता है। पश्चिम बंगाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्ययन से पता चलता है कि पिछले दशक में 55 प्रतिशत से अधिक घरों ने अंडरएज विवाहों में वृद्धि दर्ज की है। टेरेस डेस होमस के सर्वेक्षण में खुलासा हुआ कि पथर प्रतिमा और गोसाबा के 90 प्रतिशत लोग पिछले दस वर्षों में सीधे जलवायु आपदाओं का सामना कर चुके हैं, जिससे फसल उत्पादन और खाद्य सुरक्षा प्रभावित हुई है। ऐसे क्षेत्र में किशोरियों की जल्दी शादी आर्थिक बचाव की रणनीति बन जाती है। प्रवास से जोखिम और बढ़ जाता है। केवल 17 प्रतिशत प्रवासी परिवार अपने साथ पति-पत्नी को ले जाते हैं और सिर्फ 7 प्रतिशत बच्चे को ले जाते हैं, जिससे नाबालिगों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। रिपोर्टें बताती हैं कि बालिकाएं विवाह, जबरन श्रम, मानव तस्करी और विवाह प्रवासन से जुड़ी बढ़ती घटनाओं का सामना कर रही हैं।

मैदान के आंकड़े भले ही अधूरे हों, लेकिन परिणाम स्पष्ट हैं। लड़के परिवार की मदद करने के लिए स्कूल छोड़ देते हैं; लड़कियां घरेलू श्रम, जल्दी गर्भधारण, स्वास्थ्य जोखिम और सीमित गतिशीलता के चक्र में फंस जाती हैं। सर्वेक्षण के मुताबिक, 73.3 प्रतिशत विवाहित लड़कियां अन्य जिलों में पलायन करती हैं, अक्सर अजनबी समुदायों में, बिना यह सुनिश्चित किए कि उनके पति की मंशा या पृष्ठभूमि सुरक्षित भी है। गरीबी और सामाजिक हाशिए पर रहने वाले समुदाय इस संकट को और गहरा कर देते हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के घरों में 44 प्रतिशत बाल विवाह की दर दिखती है।

केनिंग के चिन्मय रे कहते हैं,'कन्याश्री जैसी योजनाएं इन द्वीपों तक नहीं पहुंच पातीं। 'प्रशासनिक बाधाएं, कड़ा दस्तावेज़ीकरण, और राजनीतिक उपेक्षा हाशिए पर रहने वाले परिवारों को लाभ नहीं दिलातीं। प्रवर्तन की कमी बच्चों को असुरक्षित छोड़ देती है और पीड़ितों को मदद नहीं मिलती।' टेरेस डेस होमस के सर्वेक्षण के अनुसार सुंदरबन की दो-तिहाई बालिकाएं अपनी शादी को पिछले आपदाओं से जोड़ती हैं। कोविड-19 लॉकडाउन ने इन समस्याओं को और बढ़ा दिया। स्कूल बंद होने से सुरक्षा की जगहें छिन गईं और बच्चे घरों में सीमित हो गए, जहां गरीबी, कर्ज और निराशा जीवित रहने की दिशा तय करती हैं। पठानखली गांव की 14 वर्षीय कल्याणी गेयन ने स्कूल छोड़ दिया, अपनी किताबें फटे कपड़े में बांधकर, क्योंकि उसकी मां फसल की विफलता के कर्ज चुकाने में संघर्ष कर रही थी। मधुपुर ढेला की 16 वर्षीय प्रिया जाना ने 2024 के तूफान में अपना घर खो दिया। खारे पानी ने खेतों को बर्बाद कर दिया। विकल्पों की कमी के कारण उसके माता-पिता ने उसके विवाह का निर्णय लिया।

स्कूल तटबंधों के साथ-साथ टूटते हैं। मौसुनी कोऑपरेटिव स्कूल, द्वीप का एकमात्र माध्यमिक विद्यालय, चिंता बढ़ाने वाली ड्रॉपआउट दर का गवाह है। प्रधानाध्यापक बिनय शि बताते हैं कि पिछले दो वर्षों में 14-18 वर्ष के लगभग 15-20 प्रतिशत छात्र स्कूल छोड़ चुके हैं, तूफानों, गरीबी और जिम्मेदारियों के दबाव में।

मत्स्य और आजीविका विशेषज्ञ डॉ. अनिमेष राय कहते हैं, 'आय बढ़ी नहीं, नावें कम हैं, और बाल विवाह दरवाजे पर खड़ा है' । बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए सैकड़ों किलोमीटर काले पानी में नाव से यात्रा करते हैं। कार्यकर्ता सर्मिष्ठा दत्ता गुप्ता कहती हैं, 'बाल विवाह कानून केवल कागज़ों पर है। लड़कियों और लड़कों के लिए न्यूनतम आयु 18 और 21 वर्ष है, लागू करना उन द्वीपों में विफल होता है, जहां सड़क की जगह नावें हैं और तूफान जीवन तय करते हैं। युवा दुल्हनें कई तरह के नुकसान झेलती हैं—उच्च जोखिम वाला गर्भधारण, एनीमिया, शिक्षा रुकना, मानसिक आघात और घरेलू बंदी। फिर भी, आशा की किरणें बची हैं। नूर स्कूल लौट गई; रूपा देवी स्वरोजगार समूह चलाती हैं; सालवीना ने दो बाल विवाह रोके; अंजलि पुलिस के साथ लड़कियों को बचाने में सहयोग करती हैं। उनका प्रतिरोध संस्थागत खामियों के बीच क्षमता की झलक दिखाता है। विशेषज्ञ जोर देते हैं कि प्रणालीगत समाधान जरूरी हैं-आपदा-प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा, बिना बाधा वाली शिक्षा, आजीविका सुरक्षा, किशोर स्वास्थ्य सेवाएं और जवाबदेह प्रवर्तन।

सुदूर द्वीपों में बाल विवाह को 'परंपरा' कहकर व्याख्यायित करना गलत है। सुंदरबन में, खारी मिट्टी, मुश्किल होता मछली पालन, टूटते तटबंध और बार-बार के चक्रवात आजीविका छीनते हैं। कमजोर आर्थिक स्थिति में जल्दी विवाह जीवन रक्षा की रणनीति बन जाता है-आपदा से निपटने की एक हताश कोशिश। लेकिन हताशा नीति की जगह नहीं ले सकती। साक्ष्य बताते हैं कि जब वित्तीय प्रोत्साहन को निरंतर शिक्षा, किशोर स्वास्थ्य सेवाओं और सामुदायिक निगरानी से जोड़ा जाता है, तब बाल विवाह में कमी आती है।

विस्थापित छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, दूरस्थ द्वीपों में कार्यशील माध्यमिक स्कूल, बाढ़ के दौरान स्वास्थ्य केंद्र, महिला प्रधान परिवारों के लिए रोजगार और मोबाइल प्रवर्तन तंत्र शामिल होना चाहिए। पर्यावरण नीति और लैंगिक न्याय में समन्वय बिना, हर तूफान प्रगति को मिटा सकता है।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

वो दवाइयां किस काम की, जिन्हें लोग खरीद नहीं सकते

डॉ. चन्द्रकान्त लहारिया

हर कुछ सालों में कोई ऐसी दवा आती है, जिसे चिकित्सा विज्ञान की बड़ी उपलब्धियों में गिना जाने लगता है। फिलहाल कीट्रूडा (पेम्ब्रोलिजुमैब) नाम की नई दवा- जो कैंसर के इलाज के लिए बनी है- को बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। लेकिन इसने एक असहज करने वाली सच्चाई को भी उजागर किया है- क्या जीवन बचाने वाली दवाएं केवल उन लोगों के लिए हैं जो उनकी कीमत चुका सकते हैं?

मर्क कंपनी द्वारा विकसित कीट्रूडा इम्यूनोथेरेपी की श्रेणी की दवा है। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर कैंसर कोशिकाओं से लड़ने में मदद करती है। फेफड़ों के कैंसर, मेलेनोमा, सर्वाइकल और किडनी कैंसर सहित कई प्रकार के कैंसर में इसका उपयोग किया जा रहा है। लेकिन भारत में कीट्रूडा का इलाज इतना महंगा है कि एक साल का खर्च एक करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। एक-एक इंजेक्शन की कीमत लाखों में है। ऐसे में यह अधिकांश मरीजों की पहुंच से बाहर है।

फिर कीट्रूडा पर पेटेंट संरक्षण होने के कारण अभी तक इसके सस्ते जेनरिक या बायोसिमिलर विकल्प बाजार में उपलब्ध नहीं हैं। इससे दवा बनाने वाली कंपनी का एकाधिकार बना रहता है और कीमतों पर कोई प्रतिस्पर्धात्मक दबाव नहीं पड़ता। कंपनियों का तर्क है कि इतनी महंगी दवाओं की कीमत उनके शोध और विकास की लागत को पूरा करने के लिए जरूरी है, लेकिन जब यही दवा वैश्विक स्तर पर अरबों डॉलर का कारोबार कर रही हो, तब यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या कीमतें वास्तव में लागत पर आधारित हैं या बाजार की ताकत पर।

भारत में स्थिति और जटिल हो जाती है, क्योंकि यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था अभी भी सीमित संसाधनों पर आधारित है। सरकारी योजनाएं भी इस तरह की महंगी दवाओं को नियमित रूप से कवर नहीं करतीं। निजी बीमा कंपनियां भी अक्सर इसकी पूरी लागत वहन नहीं करतीं।

इसके अलावा, कीट्रूडा को अभी तक आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल नहीं किया गया है, जिससे इसकी कीमत पर सरकारी नियंत्रण भी सीमित है। परिणाम यह है कि इलाज की जरूरत और इलाज की उपलब्धता के बीच एक गहरी खाई बन जाती है।

इस असमानता का एक खतरनाक परिणाम यह भी है कि कुछ मरीज सस्ती दवा की तलाश में गैरकानूनी या अनियमित बाजारों की ओर रुख करते हैं। इससे नकली या घटिया दवाओं का खतरा बढ़ जाता है, जो मरीजों की जान के लिए और भी बड़ा जोखिम बन सकता है। यह स्थिति केवल कानून-व्यवस्था की ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य नीति की विफलता को भी दर्शाती है।

कीट्रूडा से जुड़ा यह विवाद केवल एक दवा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक नैतिक प्रश्न उठाता है- क्या जीवनरक्षक दवाओं को केवल एक व्यापारिक उत्पाद के रूप में देखा जाना चाहिए क्या कंपनियों की जिम्मेदारी केवल इनोवेशन तक सीमित है या उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी दवाएं जरूरतमंदों तक पहुंच सकें? और सरकारों की भूमिका क्या होनी चाहिए?

भारत के पास इस दिशा में कुछ नीतिगत विकल्प मौजूद हैं। जरूरत पड़ने पर अनिवार्य लाइसेंसिंग के जरिए सस्ती दवाओं का उत्पादन शुरू किया जा सकता है। सरकार दवा कंपनियों के साथ मूल्य-निर्धारण पर बातचीत कर सकती है या बड़े स्तर पर खरीद कर कीमत कम कर सकती है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का दायरा बढ़ाकर ऐसी दवाओं को शामिल किया जा सकता है। आने वाले वर्षों में जब पेटेंट समाप्त होगा, तब भारतीय कंपनियों द्वारा सस्ते विकल्प लाए जाने की उम्मीद भी है, लेकिन तब तक लाखों मरीजों के लिए इंतजार करना संभव नहीं है।

एक और महत्वपूर्ण पहलू इस दवा के प्रचार-प्रसार से जुड़ा है। इसे चमत्कारी दवा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे मरीजों और उनके परिवारों में अत्यधिक उम्मीदें पैदा हो जाती हैं। जबकि सच्चाई यह है कि हर मरीज पर इसका असर समान नहीं होता। ऐसे में जरूरी है कि डॉक्टर और कंपनियां मरीजों को पूरी और संतुलित जानकारी दें, ताकि वे सही निर्णय ले सकें।

यह मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि चिकित्सा क्षेत्र में असली प्रगति क्या है। क्या केवल नई दवाएं विकसित करना ही प्रगति है, या यह सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है कि वे सभी तक पहुंच सकें यदि जीवनरक्षक दवाएं कुछ लोगों तक सीमित रहेंगी, तो यह न केवल स्वास्थ्य व्यवस्था, बल्कि सामाजिक न्याय की भी विफलता है। मेडिकल इनोवेशन का उद्देश्य केवल विज्ञान को आगे बढ़ाना नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति तक उसके लाभ को पहुंचाना भी होना चाहिए।

यदि जीवनरक्षक दवाएं कुछ लोगों तक सीमित रहेंगी, तो यह न केवल स्वास्थ्य व्यवस्था, बल्कि सामाजिक न्याय की भी विफलता है। मेडिकल इनोवेशन का उद्देश्य समाज के हर व्यक्ति तक उसके लाभ को पहुंचाना होना चाहिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

थलपति की एंट्री से त्रिकोण में उलझी तमिल राजनीति

वेद विलास यूनियल

विजय थलपति यानी कमांडर के नाम से जाने जाते हैं। विजय को लेकर दोनों गठबंधनों में खींचतान रही। लेकिन विजय ने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। तमिलनाडु मे वह कितनी सीटें जीत पाए यह कयास ही लग सकता है लेकिन वह दोनों गठबंधनों मे किसी एक का समीकरण बिगाड़ने में सक्षम हैं।

तमिलनाडु की जनता को 23 अप्रैल को जनादेश देना है। तमिलनाडु की परंपरागत सियासत से हटकर इस बार स्थिति में काफी असमंजस है। तमिलनाडु की राजनीति के दो बड़े ध्रुव डीएमके और अन्ना द्रमुक का आपसी संघर्ष इस बार अलग तरह के त्रिकोण में फंसा है। राज्य की राजनीति पर प्रभाव रखने वाले दोनों ही बड़े दलों के गठबंधन में छोटी पार्टियों के अदल-बदल की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से होती रही है। लेकिन इस बार के त्रिकोण में फिल्म से राजनीति में आए जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने अपनी नई पार्टी टीवीके को सभी सीटों पर चुनाव लड़ाकर तमिल राजनीति को अलग आयाम दे दिया है।

डीएमके के साथ इस समय कांग्रेस सहित 22 पार्टियां चुनाव मैदान में हैं। द्रमुक ने अन्ना द्रमुक के तपे तपाए नेता प्लानी स्वामी को अपने साथ जोड़कर पहला पासा फेंका है। डीएमके ने एआईडीएमके के दस साल पुराने शासन को समाप्त कर सत्ता हासिल की थी। उस समय प्लानीस्वामी ही राज्य के मुख्यमंत्री थे। अन्ना द्रमक की नेता जयललिता के निधन के बाद अन्ना द्रमुक के आंतरिक झगड़ों का लाभ द्रमुक ने भरपूर उठाया । विधानसभा चुनाव की शानदार सफलता को उसने लोकसभा में भी दोहराया। राज्य में अन्ना द्रमुक और सहयोगी बीजेपी कोई सीट हासिल नहीं कर सकी। स्टालिन ने प्रचार के परंपरागत तरीके बदले । केंद्र से भाषा और अधिकार की बात पर सीधा टकराव करके अपने को तमिल हितों का

रक्षक बताने की कोशिश की। कलेग्नार मगलीर उरीमाई थिट्टम, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, सीएम ब्रेक फास्ट स्कीम, गैस सब्सिडी जैसी योजनाएं चलाकर उन्होंने जनता को साधने की कोशिश की।

तमिल क्षेत्रीय भावनाओं को उभारने के लिए हिंदी विरोध के पुराने राग को छेड़ते हुए स्टालिन काफी आगे निकल गए। त्रिभाषा फार्मूले पर द्रमुक ने लोगों को जमकर उकसाने की कोशिश की। संकीर्ण राजनीतिक कारणों से हिंदी विरोध की जड़ों को जमकर सींचा गया। द्रमुक अहसास कराती रही है कि बीजेपी बाहरी पार्टी है। द्रमुक के लिए इस बार के चुनाव कई मायनों में आसान नहीं हैं। स्टालिन द्वारा अपने बेटे उदयनिधि को डिप्टी सीएम बनाने और सियासत में उभारने की कोशिशों के चलते पार्टी में छिपा आंतरिक विरोध दिखता है। द्रमुक सरकार के कई मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे रहे हैं। सत्ता विरोधी माहौल में नशीले पदार्थ का मुद्दा आग में घी का काम कर रहा है। कांग्रेस की राज्य में 1967 के बाद से अपनी सरकार नहीं बन सकी। भक्तवत्सलम राज्य के आखिरी कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। अन्ना दुरई के नेतृत्व में डीएमके ने कांग्रेस को पराजित किया था। इसके बाद तमिलनाडु में राष्ट्रीय पार्टियां उभर नहीं पाईं। इस दौर में कांग्रेस द्रमुक के साथ मिलकर चुनाव तो लड़ती है लेकिन द्रमुक सत्ता में उसकी भागेदारी नहीं होने देता। द्रमुक और कांग्रेस के बीच इस बार का गठबंधन बहुत गर्मजोशी के साथ नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस को अहसास है कि लोकसभा में उसकी 99 सीटों में तमिलनाडु की नौ सीटों का अपना महत्व है। इसलिए कांग्रेस दक्षिण के इस प्रमुख राज्य में अन्ना द्रमुक और बीजेपी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए द्रमुक का साथ देती है। तमिलनाडु में 234 सीटों में द्रमुक ने 164 सीटें अपने पास रखी है। कांग्रेस को पिछली बार से तीन ज्यादा 28 सीटें दी गई हैं। विजयकांत की पार्टी डीएमडीके को 10 सीटें दी गई हैं। सीपीआई और सीपीआईएम को पांच पांच सीटें दी गई हैं।

लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी अन्ना द्रमुक और बीजेपी के बीच गठबंधन को लेकर लंबा मंथन हुआ। लेकिन जयललिता के निधन के बाद लगातार कमजोर हो रही अन्ना द्रमुक के लिए यह चुनाव काफी अहम है। अन्ना द्रमुक ने बीजेपी को 27 सीटें दी हैं। पीएमके 18 एएमएमके 11 टीएमसी एम कमल के चिन्ह पर पांच सीटों पर लड़ रही है।

तमिलनाडु की दोनों पार्टियां द्रमुक और अन्ना द्रमुक द्रविड़ अस्मिता को लेकर एक लाइन रही हैं। गौरतलब है कि जयललिता के समय अन्ना द्रमुक के घोषणापत्र में राम मंदिर का जिक्र भी था। अन्ना द्रमुक द्रविड़ अस्मिता और गौरव की बात तो करती है लेकिन मुद्दों पर बहुत आक्रामक नहीं होती।

वर्ष 2004 से पहले द्रमुक एनडीए का हिस्सा था। बीजेपी की सियासी भूल में इस बात को शामिल किया जाता है कि अगर द्रमुक को एनडीए से अलग नहीं किया होता तो बीजेपी की सरकार नहीं गिरती। बीजेपी की लुक साउथ नीति में तमिलनाडु में अपना प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ाने की लक्ष्य है। बीजेपी ने दक्षिण भारत में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए काशी तमिल संगमम तमिल भाषा प्रचार जैसे कुछ चीजों पर फोकस किया।

जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवीके के सभी 239 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। वह स्वयं पेरंबूर और तिरुचिपल्ली दो सीटों पर लड़ रहे हैं। टीवीके ने 27 टिकट महिलाओं को दिए हैं। विजय थलपति यानी कमांडर के नाम से जाने जाते हैं। विजय को लेकर दोनों गठबंधनों में खींचतान रही। लेकिन विजय ने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। तमिलनाडु मे वह कितनी सीटें जीत पाए यह कयास ही लग सकता है लेकिन वह दोनों गठबंधनों मे किसी एक का समीकरण बिगाड़ने में सक्षम हैं। राज्य में सत्ता के विरोध का जो माहौल है उसमें मतदाता उन्हें विकल्प देखता है तो एनडीए के लिए मुश्किल होगी।

ITR फाइल 500/-
Whatsapp पर बनवाएं
Income Tax फाइल, GST रजिस्ट्रेशन, TDS रिफंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट
CMA DATA, MSME, BALANCE SHEET, फूड लाइसेंस
हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार है।
www.onlytds.com
सम्पर्क - शेखर गुप्ता 9300755544 - 8878655544

श्रीकंचनपथ
छत्तीसगढ़

प्रमुख खबरें

डॉ रवि शुक्ल की दिवंगत माताजी ने किया त्वचा दान

भिलाई। नेहरू नगर निवासी डॉ. रवि शुक्ला ने अपनी माताजी श्रीमती रानी शुक्ला के निधन के उपरांत परिवारजनों - मधु शुक्ला, नीलू त्रिवेदी, डॉ. मंजू शुक्ला एवं डॉ. मंजरी शुक्ला की सहमति से त्वचा दान कर एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। इस दौरान नवदृष्टि फाउंडेशन के मुकेश आढ़तिया, कुलवंत भाटिया, राज आढ़तिया, प्रभु दयाल उजाला एवं राजेश पारख पल्स हॉस्पिटल में उपस्थित रहे और पूरी त्वचा दान प्रक्रिया में सहयोग किया। सेक्टर-9 हॉस्पिटल की बर्न यूनिट टीम के डॉ. अनिरुद्ध मेने, सुनीता साहू, विनीत कुमार, शिवांगी साहू, चमेली एवं विक्की सर ने त्वचा संग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण की।

ईपीएफ नॉन-रिफंडेबल लोन हुई ऑनलाइन; सुविधा शुरू

भिलाई। बीएसपी कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से नॉन-रिफंडेबल लोन लेने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है। यह नई ऑनलाइन व्यवस्था 18 अप्रैल 2026 से प्रभावी रूप से लागू हो गई है। ऑनलाइन प्रणाली को इस तरह से तैयार किया गया है कि लोन की पात्रता को लेकर कर्मचारियों के मन में रहने वाले सभी संदेह और तकनीकी संशयों का स्वत: निराकरण हो जाएगा। कर्मचारियों को आवेदन के समय ही अपनी पात्रता की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी, जिससे कार्यालयों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी।

जगन्नाथ मंदिर में हर्षोल्लास से मनेगी परशुराम जयंती

भिलाई। राष्ट्रीय सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा श्री जगन्नाथ मंदिर, सेक्टर-6 में बैठक की गई। बैठक में राष्ट्रीय महासचिव शशिकांत तिवारी उपस्थित रहे। अध्यक्षता राष्ट्रीय सर्व ब्राह्मण समाज, जिला भिलाई के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत तिवारी ने की। सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा भगवान परशुराम जयंती 19 अप्रैल दोपहर सेक्टर-6 स्थित जगन्नाथ मंदिर परिसर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा जिसमें समाज के सभी वर्गों की सहभागिता रहेगी। बैठक में समाज के अनेक प्रतिष्ठित नागरिक एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे तथा सभी ने उनके सफल, प्रेरणादायी एवं उज्ज्वल कार्यकाल की कामना की।

परिक्षेत्र स्तरीय कर्मा जयंती पर दो जोड़ों की शादी कराई

कुम्हारी। ग्राम सांकरा परिक्षेत्र गोढ़ी में परिक्षेत्र साहू संघ के तत्वावधान में कर्मा जयंती महोत्सव और सामूहिक आदर्श विवाह का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर लगाने के अलावा दो जोड़ों का आदर्श विवाह कराया गया। मुख्य अतिथि सांसद विजय बघेल ने कहा कि समाज के कार्यों के लिए पूर्व तैयारी आवश्यक है तथा नई पीढ़ी को समाज और संस्कृति से जोड़ना हम सभी की जिम्मेदारी है। पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि समाज की शक्ति केवल संख्या में नहीं, बल्कि विचारों में होती है।

भिलाई इस्पात संयंत्र में डिजिटल प्रोजेक्ट प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। सेल- भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन (डीपीएमएस) के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए बीएमडीसी, सेक्टर-7 में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों से कुल 25 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य फोकस इंडेंटिंग विभागों अर्थात शॉप्स की भूमिका पर केंद्रित रहा, जिसमें आईपीयू की पहल से लेकर स्टेज-1 एवं स्टेज-2 अनुमोदन, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड, निष्पादन, कमीशनिंग तथा अंतत: कॉन्ट्रैक्ट क्लोजर तक की संपूर्ण प्रक्रिया को विस्तारपूर्वक समझाया गया। कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को डीपीएमएस में पंजीकरण की प्रक्रिया, डायरेक्टरी निर्माण, कंसल्टेंट को असाइनमेंट, आईपीयू निर्माण, (एमजेप्रो) के साथ डीपीएमएस का इंटरफेस तथा विभिन्न अनुमोदन प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र कार्यपालक निदेशक (परियोजनाएं) पीके सरकार की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि डीपीएमएस के सफल क्रियान्वयन हेतु सभी हितधारकों शॉप्स, कंसल्टेंट अथवा कॉन्ट्रैक्टर को प्रोजेक्ट विभाग के साथ समन्वित रूप से प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने परियोजनाओं की प्रगति का नियमित विश्लेषण करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक (परियोजनाएं) एमके गुप्ता, अनुराग उपाध्याय एवं उन्मेष भारद्वाज भी उपस्थित रहे।

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजनाएं) एमके गुप्ता ने परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए डीपीएमएस को एकीकृत मंच के रूप में अपनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए बताया कि इसमें महत्वपूर्ण गतिविधियों एवं संभावित बाधाओं के लिए अलर्ट जनरेशन जैसी विशेषताएँ उपलब्ध हैं।

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजनाएं) अनुराग उपाध्याय ने परियोजना योजना, निष्पादन एवं वाणिज्यिक पहलुओं के समेकन के साथ हितधारकों के मध्य बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर प्रकाश डाला तथा परियोजनाओं को निर्धारित समय एवं लागत के भीतर पूर्ण करने पर जोर दिया। मुख्य महाप्रबंधक (परियोजनाएं) उन्मेष भरद्वाज ने डेटा आधारित निगरानी एवं नियमित समीक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए बताया कि एसएआईएल में डीपीएमएस के कार्यान्वयन हेतु बीएसपी को नोडल इकाई के रूप में नामित किया गया है।

'जनगणना-2027' के प्रति जागरूकता लाने दुर्ग में मुनादी

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित जनगणना 2027 के अंतर्गत घर-घर सर्वेक्षण कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा व्यापक स्तर पर जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

निगम प्रशासन द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में मुनादी के माध्यम से नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है, जिसमें उन्हें जनगणना के महत्व एवं सर्वेक्षण कार्य में सहयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। नागरिकों से अपील की जा रही है कि वे अपने घर आने वाले सर्वेक्षण दल को सही एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं, जिससे यह महत्वपूर्ण कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके।

इस अभियान के तहत निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो क्षेत्रवार निगरानी करते हुए जनगणना कार्य में सक्रिय सहयोग प्रदान कर रहे हैं। अधिकारियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि सर्वेक्षण प्रक्रिया पूर्णत: पारदर्शी एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो।

स्व-गणना (Self Enumeration) की सुविधा के अंतर्गत नागरिक 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक स्वयं अपने घर से संबंधित जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए नागरिक निर्धारित लिंक https:// share. google/NVYGbDb{vMjmdoaih या शासन के आधिकारिक पोर्टल (se.census.gov.in) पर जाकर अपना गणना पत्रक भर सकते हैं। निगम प्रशासन ने सभी विभाग प्रमुखों एवं नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में स्व-गणना करने की अपील की है, ताकि जिले के लोग इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभा सकें। ऑनलाइन फॉर्म भरने के पश्चात एक विशिष्ट आईडी (Unique ID) प्राप्त होगी, जिसे 1 मई से घर-घर आने वाले प्रगणक को दिखाना अनिवार्य होगा। एक मोबाइल नंबर से केवल एक परिवार का फॉर्म भरा जा सकेगा। पोर्टल प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक खुला रहेगा।

पेवर ब्लॉक लगाने में लापरवाही पर महापौर अलका बाघमार हुईं खफा, उखाड़कर दोबारा लगाने के निर्देश

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। नगर पालिक निगम क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर महापौर अलका बाघमार ने सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार को सिविल लाइन स्थित एसपी बंगले के पीछे चल रहे पेवर ब्लॉक कार्य का उन्होंने औचक निरीक्षण किया। गंभीर खामियां पाए जाने पर खराब हिस्से को तत्काल उखाड़कर पुन: लगाने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान लोक कर्म प्रभारी देवनारायण चंद्राकर ने स्वयं मेजरिंग टेप से पेवर ब्लॉक की मोटाई, सड़क की लंबाई-चौड़ाई एवं बेस लेयर की जांच की। उप अभियंता हरिशंकर साहू को निर्माण कार्य में तकनीकी मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। महापौर ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि निरीक्षण के दौरान सभी संबंधित फाइलें साथ रखें और कार्य की नियमित मॉनिटरिंग करें। महापौर ने ठेकेदार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कार्य में गुणवत्ता से समझौता पाया गया तो भुगतान रोक दिया जाएगा तथा संबंधित एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई भी की जाएगी। निर्माण में बेस, सीमेंट एवं पानी की उचित तराई नहीं पाई गई, जो गंभीर लापरवाही है।

दो दशक बाद बीएसपी स्कूलों में फिर शुरू हुई सुरक्षा क्विज

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के सुरक्षा अभियांत्रिकी विभाग (एसईडी) द्वारा स्कूली विद्यार्थियों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सेक्टर-10 स्थित बीएसपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 9वीं एवं 10वीं के विद्यार्थियों के लिए सेफ्टी क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि इस प्रकार का आयोजन दो दशक से अधिक समय के अंतराल के बाद पुन: प्रारंभ किया गया है।

मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य महाप्रबंधक (सुरक्षा एवं अग्निशमन) देबदत्त सत्पथी, महाप्रबंधक प्रभारी (सुरक्षा अभियांत्रिकी) एसके अग्रवाल एवं महाप्रबंधक (शिक्षा) शिखा दुबे उपस्थित रहीं। जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में प्राचार्य (एसएसएस-10) श्रीमती सुमिता सरकार की उपस्थिति रही।

इस सेफ्टी क्विज में लगभग 500 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता में अग्नि सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, कार्यस्थल सुरक्षा, एर्गोनॉमिक्स, विद्युत सुरक्षा एवं पर्यावरण जागरूकता जैसे विविध विषयों को शामिल किया गया।

श्री देबदत्त सत्पथी ने दो दशक बाद इस पहल के पुनरारंभ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सुरक्षा केवल औद्योगिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि घर, सड़क एवं खेल के मैदानों में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक एवं भविष्य के नेतृत्वकर्ता के रूप में सुरक्षा मूल्यों को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने के लिए प्रेरित किया।

श्री एसके अग्रवाल ने कहा कि सुरक्षा को केवल नियमों तक सीमित न रखते हुए इसे व्यक्तिगत आदत के रूप में विकसित करना आवश्यक है। उन्होंने विद्यालय में, सड़क, घर एवं डिजिटल माध्यम जैसे चार प्रमुख परिवेशों में सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए विद्यार्थियों को कॉरिडोर में न दौड़ने, प्रयोगशाला नियमों का पालन करने, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का उपयोग करने, बिजली एवं आग से सतर्क रहने कहा।

केडी पब्लिक स्कूल के 10 विद्यार्थियों का शानदार प्रदर्शन

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। केडी पब्लिक स्कूल के कक्षा 10 के परीक्षा परिणाम इस वर्ष अत्यंत उत्कृष्ट एवं सराहनीय रहे हैं। विद्यालय के विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत और लगन से शानदार सफलता प्राप्त करते हुए विद्यालय का नाम रोशन किया है।

इस वर्ष विद्यालय का परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत रहा। अनेक विद्यार्थियों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर विशेष उपलब्धि हासिल की। इन उपलब्धियों के क्रम में - यशी देवांगन ने 94.8 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया।

झलक साहू ने 91.2 अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। लेखराज साहू ने 90 अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया।

इसके अतिरिक्त नेहल चंद्राकर 84, श्रेयश शर्मा 83.6,योगिता खारांशु 82.4, खुशी साहू 80.6, मौली 79, रागिनी साहू 77, चांदनी झा 76.4, नियति मिश्रा 74.2, निधि चंद्राकर 74, राजवीर 74, देवव्रत 73, प्राची चक्रधारी 71,अमित साहू 71 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विद्यालय को गौरवान्वित किया। सभी विद्यार्थियों का परिणाम अत्यंत उत्साहवर्धक रहा।

विद्यालय के प्राचार्य ने सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता छात्रों की कठिन मेहनत, शिक्षकों के मार्गदर्शन एवं अभिभावकों के सहयोग का परिणाम है। उन्होंने छात्रों को भविष्य में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया।

विद्यालय प्रबंधन ने सभी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है और आशा व्यक्त की है कि आने वाले वर्षों में भी इसी प्रकार के उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त होते रहेंगे.....

उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम से पल्लव ने माता-पिता के साथ ही अपने स्कूल और जिले का नाम भी किया रौशन

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। पल्लव चावड़ा ने सीबीएसई कक्षा 10वीं की परीक्षा में 94 प्रतिशत अंक प्राप्त कर एक मिसाल कायम की है। पल्लव डीएवी पब्लिक स्कूल हुडको भिलाई के छात्र हैं। उनकी इस सफलता से विद्यालय परिवार में भी हर्ष का माहौल है।

पल्लव ने बताया कि यह सफलता उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति, प्रतिदिन की कड़ी मेहनत और माता-पिता तथा शिक्षकों के प्रोत्साहन का परिणाम है। उन्होंने कहा, 'मेरे माता-पिता और शिक्षकों ने हमेशा मेरा साथ दिया और मुझे अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना सिखाया।'

ललित चावड़ा और आकांक्षा चावड़ा के पुत्र पल्लव की इस उपलब्धि पर उनके स्कूल के प्रधानाचार्य ने भी गर्व जताया। उन्होंने कहा, पल्लव हमारे स्कूल का एक होनहार और अनुशासित छात्र है। उसने न केवल उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए हैं, बल्कि अपने व्यवहार और आत्मविश्वास से अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा भी बना है। पल्लव का सपना है कि वे इंजीनियर बनें और अपने राज्य व देश के विकास में योगदान दें। उनके परिवार और शिक्षक इस सपने को साकार करने में उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं।

पल्लव ने कहा कि नियमित अध्ययन, समय का सही प्रबंधन और आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। पढ़ाई के दौरान अनावश्यक व्याकुलताओं से दूर रहना चाहिए। पल्लव चावड़ा की यह उपलब्धि यह दर्शाती है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत सच्चे मन से की जाए, तो सफलता अवश्य मिलती है।

आधुनिक कथा साहित्य की जननी हैं लोककथाएं : गुलबीर भाटिया

■ इन्टैक भिलाई-दुर्ग द्वारा 'लोक कथा-कथन' का आयोजन

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। विश्व विरासत दिवस के उपलक्ष में भारतीय सांस्कृतिक निधि (इंटैक) के दुर्ग-भिलाई अध्याय द्वारा आयोजित 'लोक कथा कथन' में 10 राज्यों के सम्बंधित लोक भाषा के जानकार साहित्यकारों ने 12 लोक कथाओं सुनाई। प्रतिष्ठित कथाकार गुलबीर सिंह भाटिया ने मुख्य वक्ता के रूप में लोक कथाओं के साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा, हम पुरखों के ऋणी हैं जिन्होंने लिपि के अभाव में भी कथा को जीवन दिया और उन्हें जीवित रखा जो आज के कथा साहित्य की जड़ भी है, मूल भी है। लोक कथाएं आज के कथा साहित्य की जननी है। उन्होंने 'एक टोकरी भर मिट्टी' को प्रवेश द्वार बताया जिससे होकर लोक कथा आधुनिक कहानी में प्रवेश करती है। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष वरिष्ठ साहित्यकार रवि श्रीवास्तव ने अध्यक्षता करते हुए कहा कि आज की कहानी लोक कथाओं की नींव पर खड़ी है। इस विरासत को सहेजने की जरूरत है ताकि लोक कथाओं की अनुगूंज सदियों तक गूंजती रहे।

आरंभ में इंटेक की दुर्ग-भिलाई अध्याय की संयोजिका डॉ हंसा शुक्ला ने अतिथियों का स्वागत करते हुए लोक कथाओं को महत्वपूर्ण साहित्यिक-सांस्कृतिक धरोहर बतलाया। संचालन करते हुए शिक्षाविद डॉ डी एन शर्मा ने कहा कि हजारों वर्षों पूर्व जन्मी लोक कथाएं हमारी अनमोल अमूर्त धरोहर हैं। उन्होंने दु:ख व्यक्त किया कि हमारी पीढ़ी की गलती से नई पीढ़ी मोबाइल के जरिए कार्टून, यू-ट्यूब, सोशल मीडिया में मस्त होकर लोक कथाओं से कट गई है।

वरिष्ठ साहित्यकार परदेसी राम वर्मा ने रंगभेद, जातिवाद, ऊंच-नीच के खिलाफ छत्तीसगढ़ी लोककथा 'करिया मुसवा पंडरा मुसवा' सुनाई। प्रतिष्ठित कवियत्री संतोष झांझी ने पंजाब में लोकप्रिय भगवान में विश्वास को स्थापित करती पंजाबी लोक कथा 'रजनी' को सुनाया। प्रसिद्ध कवियत्री विद्या गुप्ता ने मध्यप्रदेश के निवाड़ क्षेत्र में प्रचलित निमाड़ी लोककथा 'राजा भरथरी' का रोचक कथन किया। चर्चित कवि शरद कोकास ने महाराष्ट्र प्रांत की मराठी लोककथा 'बट्टे की खीर' का एकल अभिनय कर प्रस्तुति की। युवा साहित्यकार जोस एंथोनी ने केरल की एक मलयालम लोक कथा 'गोरा खरगोश' को सुनाया। कहानीकार शिवनाथ शुक्ला ने उत्तर प्रदेश में कही जाने वाली लोककथा 'सुख की मुरली दुख की मुरली' को प्रभावी ढंग से सुनाया। हिंदी व बंगाली भाषा के साहित्यकार गोविंद पाल ने बंगाल की दो भाइयों के संपत्ति बंटवारे से संबंधित बंगाली लोककथा को सुनाई। डौंडीलोहारा से आए केशव शर्मा ने राजस्थान में लोकनायक तेजा पर केंद्रित लोककथा 'वचन के पक्के' कही। रविंद्र साहू ने 'ठगराज' नामक ओडिया लोककथा सुनाई। डी नागमणि ने आंध्रप्रदेश में प्रचलित भगवान वेंकेटश्वर से जुड़ी लोककथा 'गोविंदा गोविंदा' सुनाई। डॉ डीपी देशमुख ने छत्तीसगढ़ की रोचक लोककथा ' मारे मुसुवईन ला' का कथन किया। प्रीति अजय बेहरा ने उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ से जुड़ी उड़िया 'अगहन वृहस्पति' लोककथा को बतलाया ।

आवारा श्वान के नियंत्रण के लिए प्रदेश के सभी 33 जिलों में स्थापित होगा ऐनीमल बर्थ कन्ट्रोल सेन्टर : मंत्री नेताम

अब जनजातीय क्षेत्रों के सभी महिला हितग्राहियों को मिलेगा दुधारू गाय, आय में होगी वृद्धि

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। पशुधन विकास मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि पशु जन नियंत्रण के तहत आवारा श्वानों के नियंत्रण के लिए प्रदेश के सभी 33 जिलों में नगरीय निकायों के सहयोग से एनीमल बर्थ कन्ट्रोल सेन्टर स्थापित किया जायेगा। इन सेन्टरों में श्वान जन्म को नियंत्रित करने नसबंदी अभियान चलाया जायेगा, वही श्वान के काटने से होने वाले रैबीज बीमारी को रोकने श्वानों का टीकाकरण भी किया जायेगा। मंत्री नेताम ने उक्त बातें मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान कही।

पशुधन मंत्री नेताम नें बैठक में कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जनजातीय क्षेत्रों के सभी महिला हितग्राहियों को दुधारू गाय दिया जायेगा इससे आय में वृद्धि होगी और महिलाएं आर्थिक रूप सशक्त होंगे। उन्होंने बताया कि मीठा और पौष्टिक आहार के साथ-साथ नियमित रूप से आय का साधन उपलब्ध कराने तथा दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहले हमारी सरकार दुधारू गाय वितरण की योजना बस्तर क्षेत्र के जनजातीय महिलाओं के लिए प्रारंभ किया था।

अब इसे विस्तार करते हुए राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के सभी वर्गों के महिला हितग्राहियों को दुधारू गाय दिया जायेगा। इसके लिए राज्य सरकार एनडीडीबी से समझौता किया हुआ है। उन्होंने इस योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश अधिकारियों को दिये।

मंत्री श्री नेताम ने बैठक में कहा कि प्रदेश के जलवायु के अनुकुल भारतीय नस्ल के अलग-अलग किस्मों के गायों का वितरण किया जाना सुनिश्चित हो ताकि गौ-वंशी पशुओं के साथ-साथ दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि हो सके। हितग्राही मूलक योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली पशु-पक्षियों को जरूरतमंद हितग्राहियों को चयन कर लाभान्वित भी किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पशुओं में होने वाले विभिन्न संक्रमण रोगों के नियंत्रण के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जाए जिससे आकस्मिक होने वाले पशुधन हानि को रोका जा सके।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि गौधाम योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य प्रमुख मार्गों में विचरण करने वाले घुमंतु गौ-वंशीय पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पशुओं को गौधामों में व्यवस्थापित किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि 36 गौधाम स्वीकृत कर 32 गौधाम पंजीकृत हो चुके है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि पशु संवर्धन कार्यक्रम कृत्रिम गर्भाधान एवं वत्सोंत्पादन का बेहतर क्रियान्वयन किया जा रहा है। कृत्रिम गर्भाधान का क्षेत्र विस्तार हेतु परिवहन आदि का भी सुचारू व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किये गये हैं। वहीं राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत सेक्स शॉर्टेज सीमेंन से कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2026-27 में इसके लिए हितग्राही अंशदान में छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

मंत्री नेताम ने कहा कि पशु दुर्घटना को रोकने तेजी के साथ गौधाम स्थापित कर वहां गौ-वंशों को व्यवस्थापित तथा कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा देने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती सहला निगार, संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं श्री चंद्रकांत वर्मा, कामधेनु विश्वविद्यालय के कुलपति सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थें।

उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने महिला थाना का किया लोकार्पण

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने शुक्रवार को कोरबा स्थित सिविल लाइन थाना परिसर में कोरबा जिले के प्रथम महिला थाना का फीता काटकर विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि यह थाना जिले का पहला महिला थाना होगा, जो न केवल महिलाओं के प्रति अपराधों की रोकथाम में सहायक होगा, बल्कि उनकी शिकायतों का त्वरित समाधान भी सुनिश्चित करेगा।

मंत्री देवांगन ने थाना का शुभारंभ करने के बाद निरीक्षक भावना खांडेकर को थाना प्रभारी का विधिवत पदभार ग्रहण कराया। इस थाने में थाना प्रभारी सहित बलों की पदस्थापना की गई है। मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि यह महिला थाना महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाली एक महत्वपूर्ण पहल है। इस महिला थाना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महिलाओं को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एक सुरक्षित स्थान मिल सके। इस अवसर पर मंत्री श्री देवांगन ने विभिन्न परीक्षाओं में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले इस परिवार के बच्चों को सम्मानित किया। थाना परिसर में एक वाटर कूलर की स्थापना की भी घोषणा की। साथ ही गर्मी में लगने वाले आमतौर पर आग से बचाव के उपाय हेतु पाम्पलेट का भी विमोचन किया।

इस अवसर पर महापौर संजू देवी राजपूत, जिला पंचायत के अध्यक्ष पवन सिंह, कलेक्टर कुणाल दुदावत, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, प्रीति स्वर्णकार, पार्षद अशोक चावलानी, पार्षद चंद्रलोक सिंह, योगेश जैन सहित अन्य विशिष्ट जल अधिक संख्या में उपस्थित रहे।

बंदूक से विकास की ओर

सुकमा के तुंगल इको-पर्यटन केंद्र की प्रेरक कहानी

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। सुकमा जिले में वन विभाग की एक सराहनीय पहल ने विकास और पुनर्वास की नई मिसाल पेश की है। वन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में तैयार किया गया तुंगल इको-पर्यटन केंद्र आज आत्मनिर्भरता और सामाजिक बदलाव का प्रतीक बन गया है। सुकमा नगर से मात्र एक किलोमीटर दूर स्थित यह स्थान पहले उपेक्षित और जर्जर था, लेकिन वन विभाग के प्रयासों से इसे एक सुंदर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया।

यहाँ बनाए गए आकर्षक टापू और प्राकृतिक वातावरण अब स्थानीय लोगों के साथ-साथ पड़ोसी राज्य ओडिशा से आने वाले पर्यटकों को भी आकर्षित कर रहे हैं।

इस केंद्र की सबसे खास पहल है तुंगल नेचर कैफे, जिसे 'आत्मसमर्पण पुनर्वास महिला स्वयं सहायता समूह' की 10 महिलाएँ संचालित कर रही हैं। इनमें 5 महिलाएँ वे हैं जिन्होंने नक्सलवाद का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण किया है, जबकि 5 महिलाएँ नक्सल हिंसा से प्रभावित रही हैं। इन सभी को जगदलपुर और सुकमा के संस्थानों में विशेष प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए तैयार किया गया है।

आज ये महिलाएँ आत्मविश्वास के साथ पर्यटकों का स्वागत कर रही हैं और सम्मानजनक जीवन जी रही हैं। जो महिलाएँ कभी संघर्ष और भय के माहौल में थीं, वे अब स्वावलंबन और आत्मसम्मान की मिसाल बन गई हैं।

इस पर्यटन केंद्र की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 31 दिसंबर 2025 को शुरू होने के बाद केवल तीन महीनों में, 30 मार्च 2026 तक यहाँ 8 हजार 889 पर्यटक आए। इस दौरान केंद्र ने लगभग 2.92 लाख रूपए की आय भी अर्जित की।

पर्यटक यहाँ स्वादिष्ट स्थानीय व्यंजनों का आनंद लेने के साथ-साथ तुंगल डैम में कयाकिंग, पैडल बोटिंग और बाँस राफ्टिंग जैसी रोमांचक गतिविधियों का भी अनुभव कर रहे हैं। यह पहल साबित करती है कि सही मार्गदर्शन और अवसर मिलने पर जीवन की दिशा बदली जा सकती है। तुंगल इको-पर्यटन केंद्र न केवल पर्यटन का केंद्र है, बल्कि यह उन महिलाओं के साहस, आत्मविश्वास और वन विभाग की दूरदर्शी सोच का प्रतीक है।

यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि प्रकृति संरक्षण के साथ-साथ मानव विकास को जोड़कर समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। बस्तर की बदलती तस्वीर में यह केंद्र एक उज्ज्वल उदाहरण बनकर उभरा है।

फॉरेस्ट ग्राउंड में बना बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित और अनुशासित कर रहा

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। महासमुंद जिले के ब्लॉक महासमुंद अंतर्गत फारेस्ट ग्राउंड में तैयार किया गया बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड विशेष सुविधा प्रदान करते हुए युवाओं और बच्चों को खेल के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। अगस्त 2025 में पूर्ण होकर यह मैदान आम नागरिकों और खिलाड़ियों के लिए खोल दिया गया है।

पहले शहर में बड़े खेल मैदानों की कमी और गलियों में बढ़ती वाहनों की भीड़ के कारण बच्चों और खिलाड़ियों को क्रिकेट खेलने के लिए सुरक्षित और उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाता था। निर्माण एजेंसी हाऊसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित 4842 वर्ग फुट के सीमित क्षेत्र में विकसित यह बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड एक अभिनव समाधान के रूप में सामने आया। यह स्थान की कमी को दूर करने के साथ ही आधुनिक सुविधाओं के साथ एक सुरक्षित खेल वातावरण भी प्रदान करता है।

बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड में दो पालियों में सुबह 6:00 से 9:00 बजे तक और शाम 4:00 से 8:00 बजे तक संचालित इस ग्राउंड में स्कूली बच्चे, युवा और कामकाजी लोग अपनी सुविधा अनुसार खेल का आनंद ले रहे हैं। 15-20 मिनट के छोटे फॉर्मेट में खेले जाने वाले इस खेल ने व्यस्त जीवनशैली वाले लोगों को भी फिटनेस और मनोरंजन का बेहतर विकल्प दिया है। रात में फ्लडलाइट की सुविधा के कारण खिलाड़ी कार्य के बाद भी अभ्यास कर सकते हैं। चारों ओर मजबूत नेटिंग की व्यवस्था होने से खेल सुरक्षित हो गया है तथा गेंद खोने या आसपास की संपत्ति को नुकसान पहुंचने की संभावना भी समाप्त हो गई है। कम संख्या में खिलाड़ी भी आसानी से खेल सकते हैं, जिससे यह हर आयु वर्ग के लिए उपयुक्त बन गया है। लगभग 25.07 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस परियोजना ने जिले में खेल अधोसंरचना को मजबूती दी है। यह युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित और अनुशासित कर रही है।

एन.आई.एस. क्रिकेट कोच तृपेश कुमार साहू ने बताया कि बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड में अभ्यास करने से समय की बचत होती है और खिलाड़ी कम समय में अधिक अभ्यास कर पाते हैं। इससे बच्चों की तकनीक में तेजी से सुधार हो रहा है और वे प्रतियोगिताओं के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो रहे हैं।

जल जीवन मिशन से संवरी बुलगा की तस्वीर जीवंती बाई के घर तक पहुँचा शुद्ध पेयजल

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। जल जीवन मिशन ने छत्तीसगढ़ के बुलगा जैसे गांवों में घर-घर स्वच्छ पेयजल पहुंचाकर जीवन स्तर को बदल दिया है। बुलगा गाँव में अब हर घर में नल का कनेक्शन है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को दूर से पानी लाने की मेहनत से मुक्ति मिली है।

ग्रामीण अंचलों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संचालित 'जल जीवन मिशन' अब ग्रामीणों के जीवन में खुशहाली का नया आधार बन रहा है। कभी पानी के लिए लंबी दूरी तय करने वाली महिलाओं के आंगन में आज नल से जल की धार बह रही है। इसी बदलाव की एक बानगी सरगुजा जिले के लूण्ड्रा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बुलगा में देखने को मिली है।

बुलगा निवासी श्रीमती जीवंती बाई ने बताया कि एक समय था जब पीने के साफ पानी का इंतजाम करना दिन का सबसे कठिन कार्य था। पानी के लिए उन्हें घर से काफी दूर जाना पड़ता था, जिससे समय की बर्बादी और शारीरिक थकान होती थी। पहले पानी लाने के लिए बहुत लंबा लाइन लगाना पड़ता था, लेकिन अब हमारे घर में नल का कनेक्शन लग गया है। अब सुबह और शाम दोनों वक्त नियमित रूप से शुद्ध पानी घर पर ही मिल जाता है। नल कनेक्शन लग जाने से जीवंती बाई के परिवार के समय की बड़ी बचत हो रही है।

उन्होंने बताया कि पानी लाने में जो वक्त खराब होता था, अब उस समय का उपयोग वे खेती-किसानी और अन्य घरेलू कार्यों में कर रही हैं। इससे न केवल उनकी जीवनशैली सुधरी है, बल्कि आर्थिक गतिविधियों के लिए भी अतिरिक्त समय मिल रहा है। गांव के हर घर में पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचने पर जीवंती बाई ने हर्ष व्यक्त किया है।

चिन्हारी योजना से सशक्त हो रही छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग द्वारा संचालित चिन्हारी योजना राज्य की समृद्ध लोक-संस्कृति, परंपराओं और लोक कलाकारों को नई पहचान देने का सशक्त माध्यम बनती जा रही है। इस योजना के माध्यम से न केवल पारंपरिक कला रूपों का संरक्षण हो रहा है, बल्कि कलाकारों को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से भी सशक्त किया जा रहा है।

चिन्हारी योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में लोक कलाकारों, शिल्पकारों, गायकों और नर्तकों की पहचान कर उनका पंजीयन किया जा रहा है। इससे

एक व्यापक सांस्कृतिक डेटाबेस तैयार हो रहा है, जो भविष्य में कला के संरक्षण और संवर्धन में सहायक सिद्ध होगा।

योजना के अंतर्गत चयनित कलाकारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है तथा उन्हें राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी कला प्रस्तुत करने के अवसर भी दिए जाते हैं। इसके साथ ही मेलों, उत्सवों और शासकीय कार्यक्रमों में इन कलाकारों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, जिससे उन्हें व्यापक पहचान मिल रही है।

चिन्हारी योजना से सशक्त हो रही छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृतिनई पीढ़ी को लोक संस्कृति से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन भी इस योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गुरु-शिष्य परंपरा को बढ़ावा देते हुए अनुभवी कलाकारों के मार्गदर्शन में युवाओं को पारंपरिक कला का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चिन्हारी योजना का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू विलुप्त होती लोक परंपराओं का संरक्षण और पुनर्जीवन है। इसके तहत लोक नृत्य, लोकगीत और पारंपरिक शिल्प को संरक्षित कर उन्हें नई ऊर्जा प्रदान की जा रही है। साथ ही, डिजिटल माध्यमों के जरिए इन कलाओं का प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है।

इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही, स्थानीय कला को पर्यटन से जोड़कर रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं। चिन्हारी योजना छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और कलाकारों को सशक्त बनाने की दिशा में प्रभावी साबित हो रही है।

डीएवी हुडको ने लगाई 'हाफसेंचुरी', 90 प्रतिशत के पार 50+ विद्यार्थियों ने मारी बाजी

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। डीएवी आमदीनगर हुडको, भिलाई स्थित विद्यालय ने एक बार फिर शानदार शैक्षणिक उपलब्धि हासिल करते हुए कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट परिणाम दर्ज किया है। सीबीएसई द्वारा आयोजित इस परीक्षा में विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत और लगन का बेहतरीन प्रदर्शन किया।

इस वर्ष कक्षा 10वीं की परीक्षा में कुल 248 विद्यार्थी शामिल हुए। विद्यालय का कुल परिणाम शत प्रतिशत रहा। इनमें से 90त्न से अधिक अंक प्राप्त करने वाले (52) विद्यार्थी रहे, जिनमें

प्रिया सिंह 95.4,आराध्या सिंह 96,सजल शर्मा 94, ईशान शर्मा 92.8,गगन राय 95.4,फ़ैज़ा खान 96.6, प्रभलीन कौर गिल 94.6,श्रव्य शिशिर अल्लूरवर 94.2,कुमकुम साहू 91.2,आकांक्षा सोनी 96.2,आराध्य कुमार 91.4,सुभन्रिता दत्ता 96.4,चिन्मय हर्षल जोशी 95.2,संकल्प परगनिहा 91.2, बी.पल्लवी 92.4,अनन्या साहू 90.6,रणवीर सिंह सैनी 94.8, रमेश कुमावत 90.6,दिव्यांशी यादव 90.4,टी. नितांशु 92.8, दिशा ताम्रकार 90.2,गरिमा शर्मा 90.4,श्रेया कनोजिया 90.8, हरगुन सिंह बग्गा 92.8,देवांशी रावत 95.2,नैतिक सिंह 90.4, शौर्य नेमा 95.8,सिया पांडा 95.2,अभिजीत शर्मा 97.4, अंशिका सिंह 97.2,आरव बंसल 90.2,सिद्धार्थ श्रीवास्तव 95.4, अनय यादव 92.6,रिद्धिमा नायक 93,अनन्या भट्टाचार्जी 97.2 तनिष्का जैन 95.2,आदित्य कुमार 96.8,कुशाग्र गुप्ता 97.8, वंश चंद्राकर 94.6,आयुष दत्ता 97,लवीश सुराना 94.8, बार्सिफ्त कौर भाटिया 93,सौम्या सनत 96.8,गौरव देशमुख 94.2 ,पल्लव चावड़ा 93.6,आयुष्मान दुबे 96.6,आयुष कुमार सोनी 96,स्कंधा भट्ट 96.8,प्रकृति यदु 95.2 तहमीना खान 90.8, रिशु कुमारी 90.4,स्मृति मिश्रा 90 इसी प्रकार 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले (80) विद्यार्थी रहे, जिनमें वहीं 70प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले (59) विद्यार्थी रहे,

विद्यालय के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया है और समूचे विद्यालय परिवार में हर्ष का वातावरण है।

विद्यालय के प्राचार्य प्रशांत कुमार ने सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा, इस वर्ष का यह उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम हमारे विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी निरंतर प्रयास करते हुए यह सफलता अर्जित की है। इसके साथ ही यह उपलब्धि हमारे समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन और अभिभावकों के सतत सहयोग का भी परिणाम है। विद्यालय सदैव विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध रहा है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे विद्यार्थी भविष्य में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विद्यालय एवं देश का नाम रोशन करेंगे।

मैं सभी सफल विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई एवं उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।

गांव चलो, घर-घर चलो अभियान के तहत वार्ड-13 में भाजपा का जनसंपर्क कार्यक्रम सम्पन्न

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान एवं जिला नेतृत्व के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी फाफाडीह मंडल द्वारा गांव चलो, घर-घर चलो अभियान के अंतर्गत राजीव गांधी वार्ड-13 में व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम सुनील पिल्लई एवं नवीन शर्मा के आतिथ्य में तथा वार्ड पार्षद महेंद्र खोडियार के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने घर-घर पहुंचकर केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और आमजन से संवाद स्थापित किया।

कार्यक्रम में पूर्व मंडल अध्यक्ष गोरेलाल नायक, पूर्व मंडल महामंत्री गोपाल ठाकरे, वर्तमान मंडल महामंत्री संजय शर्मा, भगवान यादव, उमा यादव, श्रीमती रजनी साहू, दशरथ साहू, भागीरथी साहू, अभिषेक साहू, रोहित पिथालिया, अनिल साहू, सदाराम बेहरा, कृष्णा राणा, राहुल बघेल, कृष्णा यादव, महेंद्र पटेल, गणेश साहू सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं वार्डवासी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान पार्टी की नीतियों और आगामी योजनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई तथा क्षेत्र के विकास के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई गई।

कई ट्रायल के बाद फाइनल हुआ लैला का लुक

गली सीरीज के लिए हंसिका मोटवानी ने की कड़ी मेहनत

फिल्म और वेब सीरीज की दुनिया में किसी किरदार को यादगार बनाने के लिए सिर्फअच्छी एक्टिंग ही काफी नहीं होती, बल्कि उस किरदार का लुक, पहनावा और पूरा व्यक्तित्व भी उतना ही मायने रखता है। दर्शक तभी उस किरदार से जुड़ पाते हैं। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए अभिनेत्री हंसिका मोटवानी ने भी अपनी आने वाली सीरीज गली की तैयारी की है। उन्होंने अपने किरदार के लिए किए गए ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर खुलकर बात की। जल्द ही प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली इस सीरीज में लैला नाम का किरदार निभाती नजर आएंगी।

उन्होंने कहा, लैला का लुक तैयार करने में काफी मेहनत लगी। यह एक बार में तय नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए कई बार ट्रायल किए गए। इस किरदार में कई अलग-अलग पहलू हैं, इसलिए उसका लुक भी उसी हिसाब से तैयार करना जरूरी था। लगभग 3 से 4 बार अलग-अलग टेस्ट करने के बाद फाइनल लुक तय किया गया। हंसिका ने कहा, लैला का स्वभाव और उसकी पर्सनैलिटी उसके लुक को तय करने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। इस किरदार में एक खास नजाकत और तहजीब है, जिसे उसके कपड़ों और स्टाइल के जरिए दिखाना जरूरी था, इसलिए उसके पहनावे को काफी सोच-समझकर डिजाइन किया गया, ताकि वह किरदार के हर पहलू को सही तरीके से दर्शा सके। मेरा मानना है कि किसी भी किरदार की पहचान सिर्फ उसके डायलॉग से नहीं, बल्कि उसके पूरे लुक से बनती है।

उन्होंने आगे कहा, इस पूरे प्रोसेस में टीमवर्क बहुत जरूरी था। मैंने और सीरीज के डायरेक्टर ने मिलकर इस लुक पर काम किया। दोनों के पास अपने-अपने विचार थे। मैंने भी अपने सुझाव दिए और डायरेक्टर ने भी अपनी सोच साझा की, जिन्हें मिलाकर एक ऐसा लुक तैयार किया गया, जो किरदार के साथ पूरी तरह फिट बैठता है। हंसिका मोटवानी ने कहा, जब कोई कलाकार अपने किरदार को अंदर से समझ लेता है, तब उसका बाहरी रूप भी अपने आप सही दिशा में ढलने लगता है। यही वजह है कि मैंने लैला के किरदार को सिर्फ निभाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे महसूस करने पर भी ध्यान दिया।

फिल्म लव एंड वॉर की रिलीज तारीख तय, संजय लीला भंसाली ने किया ऐलान

इस साल की अब तक की सबसे बड़ी घोषणा हो चुकी है। संजय लीला भंसाली निर्देशित और रणबीर कपूर, विक्की कौशल, आलिया भट्ट स्टारर मोस्ट अवेटेड फिल्म लव एंड वॉर की रिलीज डेट सामने आ चुकी है। भंसाली प्रोडक्शन ने फिल्म की रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है। फिल्म एक खास मौके पर रिलीज होगी और अब इन तीनों स्टार के फैंस के बीच भी खुशी का माहौल पैदा होने वाला है।

हाल के दशकों की सबसे बहुप्रतीक्षित रोमांटिक ड्रामा फिल्मों में से एक मानी जा रही इस फिल्म में रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट की शानदार ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, जो एक हाई-स्टेक ड्रामा पेश करेगी। बता दें, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन वीकेंड पर छाने के लिए तैयार है, जो गुरुवार, 21 जनवरी 2027 को दुनियाभर में रिलीज होगी।

भव्य स्तर पर बनी लव एंड वॉर, संजय लीला भंसाली की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी रोमांटिक

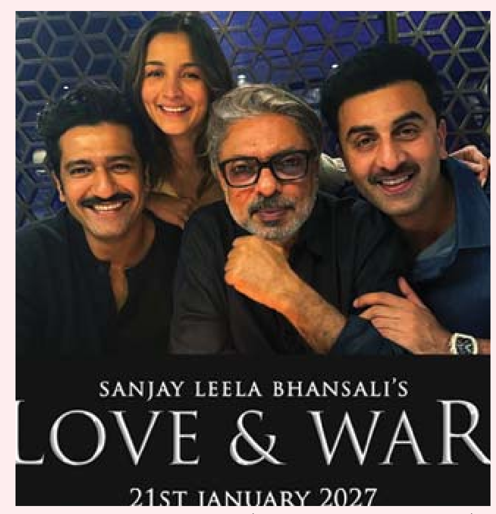

ड्रामा फिल्म बनने जा रही है। अपनी भव्य कहानी और इमोशनल गहराई के साथ, यह फिल्म भारत की सबसे बड़ी लव सागा और इंडियन सिनेमा की सबसे शानदार रोमांटिक फिल्मों में से एक बनकर उभर रही है। संघर्ष और गहरे जज्बातों की पृष्ठभूमि में सेट यह फिल्म प्यार, दोस्ती, धोखा और जुनून जैसे पहलुओं को दिखाती है, जो एक दमदार और इमर्सिव सिनेमाई अनुभव देने का वादा करती है। भंसाली की फिल्मों की वही खास पहचान, यानी ऐसी कहानी जो आपको अपनी दुनिया में डुबो दे और लाजवाब विजुअल्स यानी इस फिल्म में भी वो सब कुछ देखने को मिलेगा। उम्मीद यही है कि ये फिल्म न सिर्फ बड़े लेवल पर बनी होगी, बल्कि दुनिया भर के दर्शकों के दिल को भी गहराई से छू जाएगी।

संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी यह फिल्म, जो अपनी बारीक कहानी और शानदार विजुअल वर्ल्ड के लिए जाने जाते हैं, स्केल और गहराई दोनों का बेहतरीन मेल पेश करने की उम्मीद है। लव एंड वॉर हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी। बता दें, इससे पहले रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण दिवाली 2026 के मौके पर रिलीज होने जा रही है। फिल्म का बजट 4000 करोड़ रुपये है।

यामी गौतम से तुलना पर मेधा शंकर बोलीं-फर्क नहीं पड़ता मैं बस उनकी फैन हूं.....

अभिनेत्री मेधा शंकर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'गिन्नी वेड्स सनी 2' को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म में लीड रोल निभाने के कारण उनकी तुलना पहली फिल्म की हीरोइन यामी गौतम से हो रही है, लेकिन मेधा ने इन तुलनाओं पर साफकहा है कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेधा शंकर ने बताया, ऐसा कुछ भी नहीं है।

मैं यामी गौतम और आदित्य धर दोनों को बहुत पसंद करती हूं। उन्हें अच्छी तरह पता है कि मैं उनकी कितनी बड़ी फैन हूं। यामी हमेशा से ही एक बेहतरीन अभिनेत्री रही हैं। कभी-कभी सम्मान मिलने में थोड़ा समय लग जाता है लेकिन उनका समय जरूर आएगा। मेधा ने आगे जोड़ा, यह तुलना की बात नहीं है। मैं उन सभी लोगों से प्रेरित होती हूं जिन्होंने मुझसे पहले, बाद या साथ में बेहतरीन काम किया है।

मैंने कभी किसी से अपनी तुलना नहीं की और अगर कोई दूसरा करता भी है तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेकर्स ने फिल्म का नया गाना तुमपे ही प्यार आ गया हाल ही में जारी किया है। इस गाने का संगीत सुशांत-शंकर की जोड़ी ने मिलकर तैयार किया जबकि इसके बोल कुमार ने लिखे हैं। गाने को लेकर मेधा शंकर ने भी खुशी जाहिर की।

उन्होंने कहा, जब मैंने पहली बार यह गाना सुना, तो मैं लिरिक्स में कहीं खो सी गई थी। यह सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि प्यार के अलग-अलग रंगों को दिखाने वाला एक अनुभव है। 'गिन्नी वेड्स सनी' का पहला भाग साल 2020 में रिलीज हुआ था। इस हल्की-फुल्की रोमांटिक कॉमेडी में यामी गौतम और विक्रांत मैसी मुख्य भूमिका में थे। फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था।

अब इसके सीक्वल 'गिन्नी वेड्स सनी 2' में नई जोड़ी नजर आएगी। फिल्म में मेधा शंकर के साथ अविनाश तिवारी लीड रोल में हैं। यह फिल्म 24 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। 'गिन्नी वेड्स सनी 2' में मेधा शंकर पहली बार रोमांटिक कॉमेडी जॉनर में लीड रोल निभा रही हैं। दर्शक इस नई जोड़ी को लेकर काफी उत्सुक हैं।

पैसे निवेश करते समय न करें ये 5 सामान्य गलतियां

पैसे निवेश करने का मतलब है कि आप अपने पैसे को ऐसे तरीकों से लगाएं, जिससे वह बढ़ सकें। सही निवेश से आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। हालांकि, कई लोग बिना योजना के पैसे निवेश करते हैं और इससे उन्हें नुकसान होता है। इस लेख में हम आपको कुछ सामान्य गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए। इनका ध्यान रखने पर आपका निवेश सुरक्षित और लाभकारी हो सकेगा।

जरूरत से ज्यादा जोखिम लेना

कई लोग ज्यादा लाभ की चाह में जरूरत से ज्यादा जोखिम ले लेते हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि आपको कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए। आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता के अनुसार निवेश करना चाहिए। अधिक जोखिम लेने से आपकी पूंजी खोने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए, हमेशा संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं और अपने निवेश को अलग-अलग जगह लगाएं, ताकि जोखिम कम हो और लाभ की संभावना बनी रहे।

बिना योजना के निवेश करना

बिना योजना के निवेश करने का मतलब है कि आप बिना सोचे-समझे पैसे लगाते हैं। ऐसा करने से हो सकता है कि आपका पैसा गलत जगह पर चला जाए या फिर आपको कम लाभ मिले। इसलिए, हमेशा एक स्पष्ट योजना बनाएं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए निवेश करें। योजना बनाने से न केवल आपका पैसा सुरक्षित रहता है, बल्कि आपको बेहतर लाभ भी मिलते हैं। इसके अलावा आप जोखिमों को भी अच्छी तरह समझ पाते हैं।

सभी पैसे एक ही जगह लगाना

सभी पैसे एक ही जगह लगाने से आपका पूरा निवेश खतरे में पड़ सकता है, खासकर अगर वह जगह अस्थिर हो या नुकसान में हो। इसलिए, हमेशा अपने निवेश को विभिन्न क्षेत्रों में फैलाएं, ताकि किसी एक क्षेत्र में होने वाले नुकसान से आपका पूरा निवेश प्रभावित न हो। उदाहरण के लिए आप शेयर बाजार, जमीन-जायदाद और सोने आदि में निवेश कर सकते हैं। इससे आपके जोखिम कम होंगे और आपको बेहतर लाभ मिलेगा।

जल्दी मुनाफा निकालना

जल्दी मुनाफा निकालने की चाहत में लोग अक्सर अपने निवेश को जल्द बेच देते हैं। इससे उन्हें उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना कि उन्हें लंबे समय तक रखने पर मिलता। इसलिए, अपने निवेश को समय दें और धैर्य रखें। लंबी अवधि के लिए निवेश करने पर आपको बेहतर लाभ मिलता है। इसके साथ ही बाजार के उतार-चढ़ाव से प्रभावित होने की संभावना भी कम होती है। इसलिए, हमेशा सोच-समझकर और धैर्यपूर्वक निवेश करें।

जानकारी के बिना निवेश करना

कई लोग किसी की सलाह पर या सुनी-सुनाई बातें सुनकर बिना पूरी जानकारी लिए ही निवेश कर देते हैं, जिससे उन्हें बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए, किसी भी तरह के निवेश से पहले उसकी पूरी जानकारी जरूर लें। इसके अलावा संबंधित क्षेत्र के बारे में गहन शोध करें और विशेषज्ञों की सलाह लें, ताकि आपका निवेश सुरक्षित और लाभकारी हो सके। सही जानकारी और शोध के साथ किया गया निवेश हमेशा सुरक्षित रहता है।

क्या भारतीयों के लिए भी सही है कीटो डाइट?

जानिए पूरा सच

कीटो डाइट एक ऐसी खाने की योजना है, जिसमें शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स की बजाय चर्बी को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया जाता है। यह डाइट वजन घटाने के लिए काफी लोकप्रिय है, लेकिन क्या यह भारतीयों के लिए भी सही है? इस लेख में हम कीटो डाइट के फायदों और नुकसान पर चर्चा करेंगे, जिससे आप समझ सकें कि क्या यह आपके लिए उपयुक्त है या नहीं।

क्या है कीटो डाइट?

कीटो डाइट मुख्य रूप से अधिक चर्बी, सामान्य प्रोटीन और कम कार्बोहाइड्रेट पर आधारित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य शरीर को एक ऐसी स्थिति में लाना है, जहां वह चर्बी को ग्लूकोज के बजाय ऊर्जा के रूप में उपयोग करता है। इस डाइट में मांस, अंडे, पत्तेदार सब्जियां, नट्स और बीज शामिल होते हैं। हालांकि, इसमें चावल, रोटी और अन्य सामान्य भारतीय खाद्य पदार्थों की मात्रा बहुत कम होती है।

वजन घटाने में मददगार?

कीटो डाइट वजन घटाने के लिए काफी असरदार मानी जाती है। जब शरीर ग्लूकोज की बजाय चर्बी को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करता है तो वजन तेजी से घट सकता है। कई लोग इस डाइट को अपनाकर कुछ ही हफ्तों में अच्छे परिणाम देखते हैं। हालांकि, यह जरूरी नहीं कि हर किसी के लिए यह डाइट उतनी ही असरदार हो। कुछ लोगों को शुरूआत में ही सिरदर्द या कमजोरी महसूस हो सकती है।

स्वास्थ्य पर प्रभाव

कीटो डाइट के कई सेहत से जुड़े फायदे भी हो सकते हैं, जैसे कि रक्त शर्करा स्तर में सुधार और दिल की बीमारी का खतरा कम होना। इसके अलावा यह डाइट शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने में भी मदद कर सकती है। हालांकि, लंबे समय तक इस डाइट पर रहना मुश्किल हो सकता है और इससे जरूरी पोषक तत्वों की कमी भी हो सकती है। इसलिए इसे संतुलित तरीके से अपनाना चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

क्या सभी के लिए उपयुक्त है यह डाइट?

हर व्यक्ति की शारीरिक बनावट अलग होती है, इसलिए जो डाइट एक व्यक्ति के लिए सही हो, वह दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। भारतीय खान-पान में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अधिक होती है, ऐसे में अचानक कीटो डाइट अपनाना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों को पहले से ही किसी प्रकार की सेहत की समस्या हो सकती है, जिनके लिए यह डाइट सही नहीं हो सकती। इसलिए व्यक्तिगत जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ही कोई निर्णय लें।

क्या हैं इसके नुकसान?

कीटो डाइट के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे कि कीटो फ्लू जिसमें सिरदर्द, उल्टी, थकान आदि शामिल होते हैं। इसके अलावा लंबे समय तक इस डाइट पर रहने से जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, जिससे सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए अगर आप कीटो डाइट अपनाना चाहते हैं तो पहले अपने डॉक्टर या पोषण विशेषज्ञ से सलाह लें और संतुलित तरीके से इसे अपनाएं।

खास खबर

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के पदों पर भर्ती, ऑनलाइन आवेदन शुरू

सुकमा। एकीकृत बाल विकास परियोजना सुकमा अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए पात्र महिला अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह भर्ती प्रक्रिया विभिन्न ग्रामों के आंगनबाड़ी केंद्रों में की जाएगी। जिसके तहत ग्राम गोंडेरास के पेरमापारा केंद्र आंगनबाड़ी कार्यकता के पद रिक्त हैं। वहीं ग्राम सिरसट्टी के माण्डोपारा केंद्र में आंगनबाड़ी सहायिका के पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक एवं पात्र महिला उम्मीदवार दिनांक 16 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन माध्यम **https://aww.e-bharti.in** से आवेदन कर सकती हैं। आवेदन निर्धारित पोर्टल ई भर्ती आंगनवाड़ी पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। विस्तृत जानकारी हेतु जिला महिला बाल विकास कार्यालय या बाल विकास परियोजना कार्यालय से संपर्क कर सकते है।

3 हजार से शुरू हुआ सफर, आज 'लखपति दीदी' बनीं सोड़ी गंगी

सुकमा। जिले के कोंटा विकासखंड अंतर्गत मेड़वाही गाँव की निवासी सोड़ी गंगी ने यह साबित कर दिया है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी यदि संकल्प मजबूत हो, तो सफलता का रास्ता खुद बन जाता है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सीमित संसाधनों और चुनौतियों के बीच साधारण गृहणी जीवन जी रही सोड़ी गंगी आज अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और लगन के बल पर क्षेत्र की महिलाओं के लिए प्रेरणा बनकर उभरी हैं। कलेक्टर अमित कुमार एवं जिला पंचायत सीईओ मुकुन्द ठाकुर के मार्गदर्शन में बिहान योजना से जुड़कर उन्होंने आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिखी है।वर्ष 2020 में सोड़ी गंगी ने आदिवासी स्व-सहायता समूह से जुड़कर अपने जीवन को बदलने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया। समूह की चक्रीय निधि से मात्र 3,000 रुपये लेकर उन्होंने सिलाई कार्य शुरू किया और धीरे-धीरे अपने आत्मविश्वास को व्यवसाय में बदल दिया। इसके बाद समूह को मिले प्रथम डोज से 20,000 रुपये की सहायता लेकर उन्होंने अपने ही गाँव में किराना दुकान प्रारंभ की, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा और उनके सपनों को नई उड़ान मिली।व्यवसाय में सफलता के बाद सोड़ी गंगी ने आगे बढ़ने का साहस दिखाया और द्वितीय डोज से 1 लाख रुपये की सहायता लेकर एक ऑटो रिक्शा खरीदा, जिसे आज उनके पति सुकमा-दोरनापाल मार्ग पर चलाकर परिवार की आय बढ़ा रहे हैं। वर्तमान में सोड़ी गंगी सिलाई एवं किराना दुकान का सफल संचालन कर रही हैं और उनकी मासिक आय 10 से 12 हजार रुपये तक पहुँच गई है। डिजिटल आजीविका रजिस्टर के अनुसार उनकी वार्षिक आय 1,23,115 रुपये हो चुकी है, जिससे उन्होंने आधिकारिक रूप से 'लखपति दीदी' की श्रेणी में स्थान प्राप्त कर लिया है। इस उपलब्धि में उदय महिला संकुल स्तरीय संगठन, एरबोर की पीआरपी रुकमणी कर्मा का भी विशेष योगदान रहा, जिन्होंने समय-समय पर मार्गदर्शन प्रदान किया। सोड़ी गंगी भावुक होकर कहती हैं कि बिहान योजना ने न केवल मेरी आय बढ़ाई, बल्कि मेरे परिवार को भी मजबूती दी है।

14 अटल डिजिटल सुविधा केन्द्रों का सीएम साय ने किया शुभारंभ

70 लाख की लागत से बने केन्द्र, गांव-गांव तक पहुंचेगी ऑनलाइन सेवाएं और ई-गवर्नेंस

श्रीकंचनपथ न्यूज

कोरिया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शुक्रवार को जशपुर से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विभाग के अंतर्गत विभिन्न सड़कों के शुभारंभ एवं शिलान्यास के साथ ही कोरिया जिले को एक और महत्वपूर्ण सौगात दी। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से जिले में निर्मित 14 अटल डिजिटल सुविधा केन्द्रों का लोकार्पण किया, जो अब ग्रामीणों को आधुनिक डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। इन केन्द्रों का निर्माण वर्ष 2024-25 में स्वीकृत योजनाओं के तहत लगभग 70 लाख रूपये की लागत से किया गया है। सभी केंद्रों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और अब ये ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं के विस्तार का सशक्त माध्यम बनेंगे।

जिले के दो प्रमुख जनपद पंचायतों बैकुण्ठपुर और सोनहत में इन केन्द्रों की स्थापना की गई है। बैकुण्ठपुर जनपद पंचायत अंतर्गत जमगहना, नगर, सलबा, मुरमा, मनसुख, तेन्दुआ और डुमरिया ग्राम पंचायतों में केन्द्र बनाए गए हैं। वहीं सोनहत जनपद पंचायत अंतर्गत अकलासरई, पुसला, सोनहत, कुशहा, सुन्दरपुर, रामगढ़ और आनंदपुर ग्राम पंचायतों में डिजिटल सुविधा केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से अधिकांश केन्द्र 'क्षमता विकास योजना' के तहत बनाए गए हैं, जबकि कुछ का निर्माण राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत किया गया है।

अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित किए गए हैं। इन केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीणों को विभिन्न ऑनलाइन सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की सुविधा जाति, निवास, आय जैसे प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन डिजिटल भुगतान और बैंकिंग सेवाएं पेंशन, राशन, मनरेगा और अन्य योजनाओं से जुड़ी जानकारी ई- गवर्नेंस सेवाओं की सहज उपलब्धता अब ग्रामीणों को छोटी-छोटी सेवाओं के लिए शहर या तहसील मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा।

इन केन्द्रों के संचालन से न केवल ग्रामीणों का समय और पैसा बचेगा, बल्कि उन्हें डिजिटल रूप से सशक्त बनाने में भी मदद मिलेगी। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे, क्योंकि इन केन्द्रों के संचालन में स्थानीय स्तर पर मानव संसाधन की आवश्यकता होगी।

विकास के दो पहिए- सड़क और डिजिटल सुविधा

जहां एक ओर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अटल डिजिटल सुविधा केन्द्रों के माध्यम से उन्हें डिजिटल दुनिया से जोड़ा जा रहा है। यह दोहरा विकास मॉडल ग्रामीण जीवन को आसान और आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कोरिया जिले में 14 अटल डिजिटल सुविधा केन्द्रों का शुभारंभ ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

इससे गांवों में डिजिटल सेवाओं का विस्तार होगा और आमजन को शासन की योजनाओं का लाभ घर के पास ही मिल सकेगा। यह पहल डिजिटल इंडिया के सपने को जमीनी स्तर पर साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है।

मंत्री राजेश अग्रवाल ने 7 करोड़ की लागत से बनने वाले 120 मीटर लंबे पुल का किया भूमि पूजन

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में अम्बिकापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बड़गांवङ्कपनगोती मार्ग पर स्थित भालू नाला पर पुल निर्माण एवं पहुँच मार्ग के कार्य का आज पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने विधिवत भूमिपूजन किया ।

लगभग 7 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले इस पुल की लंबाई 120 मीटर तथा पहुँच मार्ग की लंबाई 362 मीटर होगी। इस पुल के निर्माण से क्षेत्र में आवागमन की सुविधा में उल्लेखनीय सुधार होगा और विशेष रूप से बड़गांव, पनगोती सहित आसपास के कई गांवों के निवासियों को सीधा लाभ मिलेगा। अब तक बारिश के मौसम में बाधित रहने वाला यह मार्ग पुल बनने के बाद वर्षभर सुगम और सुरक्षित रहेगा, जिससे स्थानीय जनजीवन और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

मंत्री अग्रवाल ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सड़क और पुल जैसी आधारभूत सुविधाओं के विस्तार से न केवल कनेक्टिविटी मजबूत होती है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार के अवसर भी बढ़ते हैं।

अम्बिकापुर के समग्र विकास और क्षेत्रवासियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ की गई यह परियोजना निश्चित रूप से क्षेत्र के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इस जन-उपयोगी कार्य के शुभारंभ पर क्षेत्रवासियों में उत्साह का माहौल है और उन्होंने सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है।

सुकमा में डेयरी उद्यमिता को नई उड़ान

कलेक्टर ने 3 युवाओं को स्वरोजगार हेतु दिए 2.76 लाख रुपये के अनुदान

श्रीकंचनपथ न्यूज

सुकमा। जिले में राज्य शासन की छत्तीसगढ़ राज्य डेयरी उद्यमिता योजना ग्रामीण एवं आदिवासी अंचलों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने का प्रभावी माध्यम बन रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को कलेक्टर अमित कुमार एवं उपसंचालक पशुचिकित्सा सेवाएं डॉ. संदीप इंदुरकर के मार्गदर्शन में कलेक्टर कार्यालय सुकमा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान चयनित हितग्राहियों को सहायता अनुदान राशि का वितरण किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि शासन की योजनाओं का उद्देश्य लोगों को आत्मनिर्भर बनाकर उनकी आजीविका को सुदृढ़ करना है। पशुधन विकास विभाग अंतर्गत राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजनांतर्गत जिले के 3 युवाओं को कुल 2 लाख 76 हजार 494 रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई। इसमें मुरतोंडा निवासी रमेश कुमार को 93,240 रुपये, कोंटा निवासी मड़कम विजय कुमार को 90,014 रुपये तथा कट्टम विक्रम कुमार को 93,240 रुपये की अनुदान राशि कलेक्टर अमित कुमार के हाथों प्रदान की गई।

पशु चिकित्सा विभाग द्वारा प्रदाय की गई यह राशि डेयरी व्यवसाय से संबंधित आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था में सहायक होगी, जिससे हितग्राही स्वरोजगार स्थापित कर स्थायी आय का स्रोत विकसित कर सकेंगे। कार्यक्रम के दौरान पशुपालन विभाग के अधिकारियों द्वारा हितग्राहियों को योजना के बेहतर क्रियान्वयन एवं व्यवसाय संचालन संबंधी मार्गदर्शन भी दिया गया। जिला प्रशासन के इस प्रयास से आदिवासी अंचल में रोजगार सृजन को नई गति मिलने की उम्मीद है।

5 मई तक आखिरी मौका, नहीं भरा ई-चालान तो सड़क पर ही जब्त होगा वाहन, कोर्ट की कार्रवाई तय!

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। हजारों वाहन मालिकों के लिए राहत और चेतावनी दोनों साथ आई है, यातायात पुलिस ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों के ई-चालान अब तक लंबित हैं और कोर्ट में ट्रांसफर हो चुके हैं, उनके लिए मई में लगने वाली लोक अदालत आखिरी मौका साबित हो सकती है, 17 अप्रैल 2026 को यातायात कमिश्नरेट रायपुर की ओर से जारी निर्देशों में बताया गया कि 31 दिसंबर 2025 से पहले जारी हुए सभी लंबित ई-चालानों का निराकरण लोक अदालत में किया जाएगा लेकिन इसके लिए 5 मई 2026 तक नजदीकी यातायात थाना में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, बिना रजिस्ट्रेशन के मामला लोक अदालत में जाएगा ही नहीं और फिर सीधे न्यायालयीन प्रक्रिया झेलनी पड़ेगी, पुलिस उपायुक्त यातायात विकास कुमार ने सख्त निर्देश देते हुए साफ कहा है कि लोक अदालत के बाद भी जिन मामलों का निराकरण नहीं होगा, ऐसे वाहन सीधे जब्त किए जाएंगे और कोर्ट में पेश किए जाएंगे जिससे वाहन मालिकों की मुश्किलें कई गुना बढ़ सकती हैं, यातायात पुलिस अब लंबित चालानों को लेकर पूरी तरह एक्शन मोड में है, संबंधित वाहन मालिकों को मोबाइल कॉल के जरिए सूचना दी जाएगी और व्हाट्सएप पर नोटिस भी भेजा जाएगा ताकि कोई यह न कह सके कि उसे जानकारी नहीं थी, मुख्यालय—को रजिस्ट्रेशन के लिए चिन्हित किया गया है।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक ने रचा भरोसे का नया इतिहास

श्रीकंचनपथ समाचार

7298 लाख का लाभ संचालक मंडल ने लगाई मुहर

जगदलपुर। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक जगदलपुर की वित्तीय सुदृढ़ता पर एक बार फिर भरोसे की मुहर लग गई है। 31 मार्च 2026 की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के बाद संचालक मंडल ने बैंक के प्रदर्शन को संतोषजनक और सशक्त बताया है।

गुरूवार को आयोजित संचालक मंडल की महत्वपूर्ण बैठक में बैंक के वित्तीय वर्ष 2025-26 के कार्यों और उपलब्धियों का गहन विश्लेषण किया गया। समीक्षा में सामने आया कि बैंक ने इस वर्ष 19748.39 लाख रुपये की सकल आय और 7298.08 लाख रुपये का प्रभावशाली सकल लाभ अर्जित किया है, जो बैंक के मजबूत प्रबंधन और ग्राहकों के अटूट विश्वास को दर्शाता है।

बैठक में संचालक मंडल ने बैंक की प्रगति पर संतोष जताते हुए कई दूरदर्शी और सकारात्मक निर्णय लिया। इन फैसलों का उद्देश्य बैंक की कार्यप्रणाली को और अधिक मजबूत बनाना तथा ग्राहकों को आधुनिक और बेहतर सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराना है। बैंक ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए नई योजनाओं और तकनीकी नवाचारों को अपनाने का भी निर्णय लिया है। इसके साथ ही सेवा क्षेत्र के विस्तार और विशेष रूप से कृषक सदस्यों के हितों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया, ताकि उन्हें सरल और बेहतर बैंकिंग सेवाएं मिल सकें।

संचालक मंडल ने इस उपलब्धि के लिए बैंक के अधिकारियों, कर्मचारियों और ग्राहकों के सहयोग को सराहते हुए भविष्य में और भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई। बैठक में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, उपाध्यक्ष श्रीनिवास मिश्रा, नाबार्ड प्रतिनिधि, सीईओ जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक कुंवर सिंह ध्रुव, उपायुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, उप संचालक कृषि, लेखा विशेषज्ञ चार्टड अकाउन्टेड प्रतीक चिखलीकर, विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केन्द्र धर्मपाल केरकेट्टा सहित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

माओवाद की समाप्ति के बाद अब बस्तर का सर्वांगीण विकास होगा

माओवाद की समाप्ति के बाद अब बस्तर का सर्वांगीण विकास होगा

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने कांकेर जिले के दुर्गूकोंदल ब्लॉक मुख्यालय में सर्व आदिवासी समाज कल्याण विश्राम गृह का लोकार्पण किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि पिछले 04 दशक तक हिंसा, आतंक का पर्याय बन चुका माओवाद आज समाप्त हो गया है। लंबे अरसे तक दंश झेलने वाले बस्तर में अब तेजी से सर्वांगीण विकास होगा।

दुर्गूकोंदल के बाजार चौक में आयोजित मंचीय कार्यक्रम में मंत्री श्री नेताम ने कहा कि प्रदेश में माओवाद की समूल समाप्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प को पूरा करने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बेहतर रणनीति के साथ इस कार्य को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि साय सरकार के नेतृत्व में युवा, बुजुर्ग, बच्चे और महिलाओं सभी वर्ग के लिए बेहतर कार्य हो रहे हैं। बस्तर के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा मास्टर प्लान तैयार किया गया है। श्री नेताम ने सर्व आदिवासी समाज विश्राम गृह की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इससे समाज के लोगों को लाभ मिलेगा और सामाजिक गतिविधियों को अच्छे ढंग से संपादित कर सकेंगे। इस अवसर पर विधायक श्रीमती सावित्री मंडावी ने भी समाज जनों को बधाई देते हुए विश्राम भवन के निर्माण को दुर्गुकोंदल क्षेत्र के लिए काफी उपयुक्त बताया।

उल्लेखनीय है कि बाजार चौक दुर्गूकोंदल में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कांकेर द्वारा पीएसी मद से 43 लाख 08 हजार रुपए की लागत से उक्त भवन तैयार किया गया है, जिसका लोकार्पण आज आदिम जाति विकास मंत्री श्री नेताम ने किया। इसके पहले, उन्होंने भानुप्रतापपुर के विश्राम गृह में स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर क्षेत्र के समस्याओं की जानकारी ली तथा यथोचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

यूरिया का प्रभावी विकल्प बन रही हरी खाद जशपुर में 600 हेक्टेयर में प्रदर्शन

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में टिकाऊ और जैविक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इसी क्रम में जशपुर जिले में रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के उद्देश्य से हरी खाद के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

कृषि विभाग द्वारा जशपुर जिले के सभी विकासखंडों में इस वर्ष 600 हेक्टेयर क्षेत्र में हरी खाद का प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों से अपील की गई है कि वे कृषि विभाग के मैदानी अमले से संपर्क कर हरी खाद तकनीक अपनाएं, जिससे मिट्टी की सेहत में सुधार के साथ दीर्घकालीन उत्पादकता सुनिश्चित हो सके। हरी खाद के अंतर्गत ढेंचा, सनई, मूंग, उड़द और बरसीम जैसी फसलों को खेत में उगाकर 40 से 50 दिन बाद जुताई कर मिट्टी में मिला दिया जाता है। इसके पश्चात 2 से 3 सप्ताह बाद मुख्य फसल की बुवाई की जाती है। यह प्रक्रिया मिट्टी में प्राकृतिक पोषक तत्वों की पूर्ति करती है।

हरी खाद के उपयोग से मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटाश एवं अन्य आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है, साथ ही जैविक पदार्थों में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी की जलधारण क्षमता बेहतर होती है और भूमि भुरभुरी एवं अधिक उपजाऊ बनती है। हरी खाद अपनाने से रासायनिक उर्वरकों, विशेषकर यूरिया, की आवश्यकता में कमी आती है।

विशेषज्ञों के अनुसार, हरी खाद का उपयोग कम लागत में अधिक लाभ देने वाला उपाय है, जो पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायक है। राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में किए जा रहे प्रयास किसानों को आत्मनिर्भर और खेती को अधिक टिकाऊ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं।

खास खबर

ढाबे से 160 लीटर डीजल जब्त, संचालक गिरफ्तार

रायगढ़। तमनार थाना क्षेत्र के गारे गांव में ढाबे के पीछे अवैध रूप से डीजल का भंडारण सामने आया है। पुलिस ने अपना ढाबा में कार्रवाई कर 160 लीटर डीजल जब्त किया और संचालक को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि डीजल को प्लास्टिक जरीकेनों में भरकर रखा गया था और वहां किसी प्रकार के सुरक्षा इंतजाम नहीं थे। पुलिस के मुताबिक सूचना मिली थी कि ढाबा संचालक द्वारा ज्वलनशील पदार्थ का अवैध भंडारण कर रखा गया है। टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। ढाबे के पीछे रखे 50-50 लीटर के दो जरीकेन और 35 व 25 लीटर क्षमता के जरीकेनों में कुल 160 लीटर डीजल मिला, जिसकी कीमत करीब 16 हजार रुपए आंकी गई है। इस दौरान तत्काल जब्ती और गिरफ्तारी की कार्रवाई की।

पागल कुत्ते का आतंक, चार साल के बच्चे सहित कई लोग घायल

बालोद। बालोद जिले के डौंडी लोहारा थाना क्षेत्र के चिल्हाटीखुर्द गांव में एक पागल कुत्ते ने जमकर आतंक मचाया। कुत्ते ने पहले गांव के मवेशियों पर हमला किया और फिर राहगीरों को निशाना बनाया। इसी दौरान गांव में खेल रहे एक 4 वर्षीय मासूम पर भी उसने हमला कर दिया, जिससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि कुत्ते ने बच्चे को करीब 17 जगहों पर काटा, जिससे उसकी हालत चिंताजनक हो गई। लगातार हो रहे हमलों से गांव में दहशत का माहौल बन गया था। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने अंततः पागल कुत्ते को घेरकर पीट-पीटकर मार डाला। फिलहाल घायल बच्चे का इलाज जारी है और गांव में इस घटना के बाद डर का माहौल बना हुआ है।

ऑपरेशन शांति में कोरबा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 48 वारंटी की गिरफ्तारी

कोरबा। जिले में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए कोरबा पुलिस द्वारा सजग कोरबा, सतर्क कोरबा अभियान के तहत चलाए गए ऑपरेशन शांति में बड़ी सफलता हासिल हुई है। दो दिनों के विशेष अभियान में पुलिस ने कुल 48 फरार वारंटियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों लखन पटले एवं नीतिश ठाकुर के मार्गदर्शन में जिलेभर में सघन अभियान चलाया गया। इस दौरान सभी थाना और चैकी प्रभारियों को विशेष निर्देश दिए गए थे, जिसके तहत पुलिस टीमों ने अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। इसके अलावा, जिले में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विशेष चेकिंग अभियान भी चलाया गया। इस दौरान मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 24 लोगों के खिलाफ शराब पीकर वाहन चलाने पर कड़ी चालानी कार्रवाई की गई।

अफेयर के शक में बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को मार-डाला

किराए के कमरे में गला घोंटा, पुलिस को बोला- बेहोश है, अस्पताल ले जाओ

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बॉयफ्रेंड ने गला घोंटकर अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। उसे शक था कि, प्रेमिका का किसी दूसरे के साथ अफेयर चल रहा है। इस बात पर दोनों का विवाद हुआ और गुस्से में आकर कार्तिक ने उसे मार डाला। उसके बाद खुद ही पुलिस को फोन कर मर्डर की जानकारी दी। घटना पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र का है।

मिली जानकारी के मुताबिक, युवती की पहचान यूनेश्वरी वर्मा (26) है, जो कि मूल रूप से खैरागढ़ जिले के चिचोला की रहने वाली थी। वह दुर्ग में पढ़ाई करती थी। आरोपी बॉयफ्रेंड कार्तिक राम साहू (27) बालोद जिले का रहने वाला है। पढ़ाई के दौरान दोनों की पहचान हुई ।

दरअसल, यूनेश्वरी वर्मा पढ़ाई के लिए पुलगांव में किराए के मकान में रह रही थी, जबकि कार्तिक भी सुभाष नगर में किराए के मकान में रहता था। दोनों दुर्ग-बालोद रोड स्थित कोलिहापुरी के बीएम कॉलेज में बी.एड की पढ़ाई कर रहे थे। इसी दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। हालांकि कार्तिक यूनेश्वरी पर शक करता था कि, उसका किसी दूसरे के साथ अफेयर चल रहा है। इसी बातकर लेकर दोनों में अक्सर विवाद होता था। शुक्रवार (17 अप्रैल) करीब दोपहर एक बजे कार्तिक यूनेश्वरी को लेकर अपने रूम पहुंचा, जहां उसी बात पर उनका दोबारा विवाद हो गया। गुस्से में आकर कार्तिक ने यूनेश्वरी का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद कार्तिक ने खुद ही पूरे मामले की जानकारी डॉयल-112 पर दी। टीम मौके पर पहुंची तो उसने कहा- 'देखिए साहब, यह बेहोश हो गई है, उठ नहीं रही।' स्थिति को देखते हुए डायल 112 की टीम ने युवती को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और शव का पंचनामा कर पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेजवा दिया है। आज पोस्टमॉर्टम किया जाएगा। पूछताछ में आरोपी अपना जुर्म स्वीकार लिया है।

घटना स्थल से जुटाए अहम साक्ष्य

पुलिस टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने मौके से महत्वपूर्ण सबूत जुटाए हैं, जो मामले को मजबूत बनाने में जरूरी होंगे। कमरे की स्थिति और अन्य परिस्थितियों से भी हत्या की पुष्टि हुई है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 103(1) बीएनएस के तहत केस दर्ज गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

जवान के साथ लाखों का फ्रॉड बैंक कर्मचारी पर केस दर्ज

श्रीकंचनपथ समाचार

बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां देश की सुरक्षा में तैनात एक आर्मी जवान के साथ लाखों रुपये की ठगी कर दी गई। अर्जुन्दा थाना क्षेत्र के ग्राम ओडारसकरी निवासी जवान ने गुंडरदेही स्थित एक निजी बैंक में केवल 2 लाख के लोन के लिए आवेदन किया था, लेकिन बैंक कर्मचारी की कथित चालबाजी से उसके नाम पर 17 लाख का लोन निकाल लिया गया।

आरोप है कि बैंक में पदस्थ कर्मचारी रेखराम साहू ने दस्तावेजों में हेरफेर कर बड़ी रकम का लोन पास करवा दिया। जैसे ही लोन की राशि खाते में आई, उसमें से 15.50 लाख तुरंत किसी अन्य खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। जवान उस समय जम्मू-कश्मीर में पोस्टेड था, जिससे उसे इस धोखाधड़ी की भनक तक नहीं लगी।

ठगी का खुलासा तब हुआ, जब बैंक की ओर से लोन की भारी किस्त जमा करने का दबाव बनाया गया। हैरान जवान को पता चला कि उसने तो केवल 2 लाख के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसके नाम पर 17 लाख का कर्ज चढ़ा दिया गया है। इसके बाद उसने तत्काल गुंडरदेही थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी बैंक कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे ट्रांजेक्शन और दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि सच्चाई सामने लाई जा सके और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके।

मास्टरमांइड बाबू खेमानी सहित 27 सट्टेबाज गिरफ्तार

सट्टा एप से जुड़ा इन्फ्लुएंसर खेमानी गोवा से चला रहा था पैनल

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। दूसरे राज्यों में बैठकर सट्टेबाजी का नेटवर्क चलाने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मास्टरमाइंड बाबू खेमानी को पुलिस ने गुरुवार को मुंबई में छापा मारकर गिरफ्तार किया है। आरोपी के पकड़े जाने के बाद मुंबई व गोवा में ऑपरेशन चलाया गया, जहां से 6 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सभी को रायपुर लाया गया है।

पुलिस ने पूछताछ के बाद बाबू खेमानी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से अब तक 150 से ज्यादा खाते और सिम कार्ड मिले हैं। इन खातों में 15 करोड़ से अधिक का ट्रांजेक्शन सामने आया है, जिसकी जांच की जा रही है। अब तक इस गिरोह के 27 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाबू खेमानी का भाई और सरगना करण खेमानी फरार है। उसके विदेश भागने की चर्चा है।

इसमें कुछ बड़े सटोरी भी मोबाइल बंद कर अंडरग्राउंड हो गए हैं। पुलिस के अनुसार, आमानाका मारुति इन्क्लेव निवासी गुलशन खेमानी उर्फबाबू सट्टेबाजी का मास्टरमाइंड है। उसने अलग-अलग सट्टेबाजी एप चलाने वाले बड़े बुकियों को जोड़कर नया सिंडिकेट बनाया और पैनल का प्रचार-प्रसार किया। इन पैनलों में आईपीएल क्रिकेट में रोजाना करोड़ों का दांव लग रहा है। सिंडिकेट में सभी का काम बंटा हुआ है। इसमें सभी को कमीशन दिया जा रहा है। दूसरे राज्यों में बैठकर छत्तीसगढ़ में लिया जा रहा दांव पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए अधिकांश बड़े बुकियों ने राज्य छोड़ दिया है या दूसरे राज्यों में किराए के मकान, फ्लैट और रिसॉर्ट लेकर वहां से नेटवर्क चला रहे हैं। इसे संचालित करने के लिए अलग-अलग राज्यों के युवकों को नौकरी पर रखा गया है। उन्हें 25-30 हजार रुपए वेतन दिया जा रहा है। सिंडिकेट में हर ग्रुप और व्यक्ति का काम बंटा हुआ है। उस अनुसार उनका कमीशन भी तय है।

इंस्टा पर रील, पर्दे के पीछे डील: फॉलोअर्स को मैसेज भेज सट्टे की लत लगा रहा था बाबू खेमानी

सट्टेबाजी में गिरफ्तार गुलशन उर्फ बाबू खेमानी रायपुर का कारोबारी है। उसकी रवि भवन में मोबाइल की बड़ी दुकान है। इसके अलावा परिवार का अन्य कारोबार भी है। कारोबारी होने के साथ बाबू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है। कई राजनेताओं, संतों और अभिनेताओं के साथ उसकी तस्वीरें हैं। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर उसके 2.59 लाख फॉलोअर्स हैं। डीसीपी क्राइम स्मृतिक राजनाला ने बताया कि बाबू अपने फॉलोअर्स को व्यक्तिगत मैसेज कर सट्टेबाजी का प्रमोशन कर रहा था। लोगों को दांव लगाने का लालच दे रहा था।

अब ऐसे समझिए किस तरह चल रहा था नेटवर्क

■ डिजिटल पैनल व आईडी: सट्टे के लिए ऑनलाइन पैनल 18-20 लाख रुपए में बेचा जा रहा है। आईडी और पासवर्ड 10 हजार से 1 लाख रुपए में दिए जा रहे हैं। 10 हजार से अधिक लोगों ने आईडी ली है।

■ हवाला से लेन-देन: सट्टे की रकम को ठिकाने लगाने के लिए हवाला नेटवर्क और फर्जी खातों का उपयोग किया जा रहा है।

■ इंटरनेशनल लिंक: बाबू का कनेक्शन दुबई समेत खाड़ी देशों के सट्टा किंगपिन से है।

रायगढ़ में सांभर का शिकार, 5 आरोपी को किया गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ समाचार

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सांभर का शिकार कर उसका मांस घर में पकाया जा रहा था। इस मामले में वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए 5 शिकारियों को गिरफ्तार किया और मांस जब्त किया। मामला रायगढ़ रेंज का है। दरअसल गुरुवार को वन अमले को सूचना मिली कि देलारी गांव में वन्यप्राणी का मांस पकाकर खाने की तैयारी की जा रही है। सूचना मिलते ही वनकर्मी तुरंत गांव पहुंचे। कई घरों की तलाशी के दौरान देलारी निवासी आत्माराम, मायराम, हरिश्चंद्र साव

और तरुण के घर से सांभर का पका हुआ मांस बरामद हुआ। वन अमले ने मांस को जब्त कर लिया है। मोतराम राठिया के घर की जांच के दौरान पता चला कि वह करीब 1 किलो मांस पकाकर खा चुका है। इसके बाद वन अमले ने पका हुआ मांस और बर्तन जब्त किए। सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर रेंज कार्यालय लाया।

पूछताछ में आरोपियों ने सांभर का मांस पकाने की बात स्वीकार की। इसके बाद वन अमले ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के उल्लंघन पर धारा 39, 50, 51 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। एसडीओ तन्मय कौशिक ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि देलारी गांव में सांभर का मांस पकाया जा रहा है। इसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी। गांव के घरों की जांच करने पर 5 घरों में सांभर के अवशेष मिले।

कई जगह मांस पहले ही पकाया जा चुका था। वन अमले ने मांस के सैंपल लेकर लैब भेजने की प्रक्रिया शुरू की। पूछताछ में ग्रामीणों ने जंगल में शिकार करने की बात स्वीकार की। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।

4 ट्रकों से 34 लाख का कबाड़ जब्त, आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पुलिस ने अवैध कबाड़ परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। छाल से घरघोड़ा की ओर कबाड़ का अवैध परिवहन किया जा रहा था, जिसे पुलिस ने नाकेबंदी कर पकड़ा। कार्रवाई के दौरान 4 ट्रकों से 81.02 टन कबाड़ जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीब 34.13 लाख रुपए है। ट्रकों समेत कुल 82.13 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई। मामला छाल थाना क्षेत्र का है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि हाटी से छाल होते हुए घरघोड़ा की ओर अवैध कबाड़ ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर छाल पुलिस टीम ने थाना के सामने बैरियर लगाकर नाकेबंदी की और संदिग्ध ट्रकों की जांच शुरू की। जांच के दौरान चालक छोटे लाल यादव, निवासी गोकुलगंज सीतामणी, थाना सिटी कोतवाली, जिला कोरबा को रोका गया। ट्रक में लगभग 25 टन 100 किलोग्राम लोहा, पाइप, एंगल और स्क्रैप लोड था, जिसकी कीमत करीब 10.52 लाख रुपए और वाहन की कीमत लगभग 12 लाख रुपए आंकी गई। चालक से दस्तावेज मांगे गए, लेकिन कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाने पर पुलिस ने कुल 22.52 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली।

इसके बाद पुलिस ने एक अन्य संदिग्ध ट्रक को पकड़ा, जिसे चालक नरसिंग यादव, निवासी भदरापारा, बाल्को थाना, जिला कोरबा चला रहा था। वाहन में करीब 24 टन 100 किलोग्राम कबाड़ लोड था। इसकी अनुमानित कीमत 10.37 लाख रुपए और ट्रक की कीमत करीब 12 लाख रुपए आंकी गई। दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर कुल 22.37 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई।

इन सभी मामलों में किसी भी चालक ने वैध दस्तावेज पेश नहीं किए गए। सभी कार्रवाईयों को मिलाकर कुल 81.02 टन स्क्रैप जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि स्क्रैप और वाहनों सहित कुल 82.13 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई है।

बिलासपुर के मजदूरों को महाराष्ट्र में बंधक बनाकर पीटा

श्रीकंचनपथ समाचार

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के मजदूर परिवार को महाराष्ट्र के पुणे में बंधक बनाकर ठेकेदार ने साथियों के साथ मिलकर मारपीट की है। जिससे परिवार के कई लोगों का सिर फट गया है। ससुर को बंधक बना लिया। वहां लोकल थाने में शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मजदूर की महिला रिश्तेदार किसी तरह ठेकेदार और उसके गुर्गों के चंगुल से भागकर बिलासपुर पहुंची।

जिसके बाद उसने एसएसपी से शिकायत कर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इसके साथ ही अपने रिश्तेदार को सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगाई है। दरअसल, महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले लेबर ठेकेदार भुवनेश्वर राय और सुरेंद्र राय नवंबर 2025 में बिलासपुर आया था। उसने पचपेड़ी थाना क्षेत्र के सुकुलकारी निवासी संतोष महिलांगे, उसकी पत्नी, रिश्तेदार कलाबाई भार्गव सहित परिवार के सदस्य और रिश्तेदारों को काम दिलाने का दावा किया।

प्रेग्नेंट महिला का इलाज कराने नहीं दिए पैसे

संतोष के दामाद दिलकुमार भार्गव ने बताया कि, उसकी सास प्रेग्नेंट है, जिसका इलाज कराने के लिए पैसों की जरूरत थी। उन्होंने लेबर ठेकेदार से पैसे की मांग की, जिस पर वो गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर जमकर मारपीट की, जिससे परिवार के कई लोगों का सिर फट गया।

इस विवाद के बाद घायल मजदूर मामले की शिकायत लेकर स्थानीय पुलिस के पास पहुंचे। लेकिन, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दिल कुमार ने बताया कि, जब परिवार के सदस्य बीमार हुए, तब ठेकेदार भुवनेश्वर राय और सुरेंद्र राय से अपने हक की मजदूरी मांगी, तो वे भड़क गया।

संतोष को गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और उसे जबरन कैद कर लिया गया। डरा-सहमा परिवार अब अपने मुखिया को सही सलामत लाने की मांग कर रहा है। सोशल मीडिया पर मजदूरों के साथ मारपीट करने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में ठेकेदार और उसके साथी मजदूरों पर दबाव बनाते और मारपीट करते दिख रहे हैं। इसी वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान और लोकेशन ट्रेस कर रही है। पीड़ित परिवार ने एसएसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस की सलाह पर उन्होंने श्रम विभाग में भी सूचना दे दी है। पुलिस और प्रशासन अब महाराष्ट्र पुलिस के संपर्क कर बंधक श्रमिक को सुरक्षित वापस लाने की तैयारी कर रही है।

बिलासपुर में कार से 1.22 करोड़ का गांजा पकड़ाया

श्रीकंचनपथ समाचार

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एसीसीयू की टीम ने एक कार से 1.22 करोड़ रुपए कीमती 245 किलो गांजा बरामद किया है। नेशनल हाईवे पर पुलिस को देखकर तस्कर गांजा लेकर भाग रहे थे, जिसका पीछा कर टीम ने उन्हें दबोच लिया। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा भाग निकला। घटना रतनपुर थाना क्षेत्र की है।

दरअसल, शुक्रवार को एसीसीयू प्रभारी निमितेश सिंह को जानकारी मिली थी कि, गांजा तस्कर कटघोरा से बिलासपुर होते हुए मरवाही मार्ग से मध्यप्रदेश जा रहे हैं। उनके पास बड़ी मात्रा में गांजा रखा हुआ है। पुलिस को मुखबिर ने बकायदा मारुति अर्टिगा (सीजी 04 क्यूडी 7255) में गांजा तस्करी होने की जानकारी दी।

इस पर एसीसीयू और रतनपुर पुलिस ने भेड़ी मुड़ा नवापारा चौक पर घेराबंदी की। इस दौरान जैसे ही संदिग्ध कार वहां पहुंची, पुलिस को देख चालक ने यू-टर्न लेकर भागने की कोशिश की। पुलिस की दो टीमें अलग-अलग

वाहनों से पीछा करने लगीं।

भागते समय तस्कर ने कार रॉन्ग साइड पर मोड़ दी। पीछा कर रही टीम के एक जवान ने ड्राइवर साइड पर डंडा मारा, जिससे कार का संतुलन बिगड़ा और वह रुक गई। इस दौरान एक तस्कर कार से उतरकर भाग गया, जबकि दूसरे को मौके पर पकड़ लिया गया। कार की जांच में काले शीशों के पीछे बड़ी मात्रा में गांजे के पैकेट मिले। कुल 245 किलो गांजा बरामद किया गया।

पुलिस ने कार समेत करीब 1.30 करोड़ रुपए का सामान जब्त किया है। आरोपी के खिलाफएनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। एसएसपी ने इस कार्रवाई में शामिल टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है।

ओडिशा कनेक्शन और एमपी सप्लाई की जांच

गिरफ्तार आरोपी अमित कुमार केवट मध्य प्रदेश के शहडोल के बुढार का निवासी है। पूछताछ में उसने शुरू में पुलिस को गुमराह किया, लेकिन बाद में बताया कि गांजा कटघोरा मार्ग से मध्य प्रदेश ले जाकर खपाया जाना था। पुलिस अब ओडिशा और मध्य प्रदेश कनेक्शन के साथ मुख्य सरगना की तलाश कर रही है।

दो गाड़ियों में थी खेप, एक निकल गई

पुलिस को सूचना मिली थी कि, दो गाड़ियों से गांजा ले जाया जा रहा है। कार्रवाई में एक कार पकड़ी गई, जबकि दूसरी कार में सवार तस्कर फरार हो गए। पुलिस देर रात तक पकड़े गए आरोपी से दूसरी गाड़ी के बारे में पूछताछ करती रही। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

हत्या का प्रयास, आरोपी को पांच साल की कैद

कोरबा। कोरबा के पसान थाना के अमझर गांव में 5 साल पहले टंगिया से हमला कर हत्या के प्रयास में आरोपी को 5 साल कैद की सजा हुई है। घटना 10 जून 2021 की रात 9.30 बजे की है। अमझर निवासी संतलाल उर्फसंतराम यादव (40) ने गांव के बलराम यादव के घर पहुंच कर उस पर टंगिया से हमला किया था।

बलराम गंभीर रूप से घायल हो गया था। पसान पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी संतलाल को गिरफ्तार किया था। प्रकरण की सुनवाई द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा कोर्ट में चल रही थी। शासकीय लोक अभियोजक कटघोरा दिलीप झा की ओर से पैरवी की जा रही थी।

प्रमुख खबरें

'मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2026' हेतु आवेदन आमंत्रित

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग द्वारा राज्य की समृद्ध लोक कला एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2026' के अंतर्गत प्रदेशभर के लोक कलाकारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना के माध्यम से लोकनृत्य, लोकगायन, लोकनाट्य, छत्तीसगढ़ी गीतकार, वाद्ययंत्र वादक, शिल्प कलाकार, पारंपरिक पाक कला एवं सौंदर्यकला से जुड़े कलाकारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें सम्मानित करने की पहल की गई है, ताकि वे अपनी कला को निरंतर आगे बढ़ा सकें और सांस्कृतिक परंपराएं जीवंत बनी रहें। योजना के तहत चयनित कलाकारों को प्रतिवर्ष न्यूनतम 12 हजार रुपये से लेकर अधिकतम 24 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि ई-पेमेंट के माध्यम से दी जाएगी। इस योजना का लाभ उन्हीं कलाकारों को मिलेगा जिनकी सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय 96 हजार रुपये से अधिक नहीं है। साथ ही, चयनित कलाकारों को एक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार यह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी और आगामी दो वर्षों तक वे पुनः इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। आवेदन के लिए निर्धारित प्रारूप में अपनी पूरी जानकारी देना अनिवार्य है, जिसमें नाम, कला विधा, पता, जिला, मोबाइल नंबर, चिन्हारी पोर्टल का पंजीयन क्रमांक, अनुभव के वर्ष तथा उपलब्धियों का विस्तृत विवरण (प्रमाण पत्र, फोटो, वीडियो आदि सहित) शामिल है। साथ ही चिन्हारी पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य रखा गया है। इच्छुक कलाकार निर्धारित प्रारूप में आवेदन भरकर पंजीकृत डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन पत्र भेजने की अंतिम तिथि 15 मई 2026 है। लिफाफे पर 'मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2026' अंकित करना होगा। अधिक जानकारी विभागीय वेबसाइट www.cgculture.in पर भी प्राप्त की जा सकती है। इस योजना के माध्यम से संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन लोक कलाकारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य कर रहा है बल्कि कला को संरक्षित भी कर रहा है।

'नवा तरिया, आय के जरिया' के तहत 500 नए तरिया निर्माण का शिलान्यास

'मोर गांव, मोर पानी, मोर तरिया' महाअभियान अंतर्गत 500 नए तरिया का मुख्यमंत्री साय ने किया शिलान्यास

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी पहल 'मोर गांव, मोर पानी, मोर तरिया महाअभियान' का आज जशपुर के रणजीता स्टेडियम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुभारंभ किया। अभियान के अंतर्गत 'नवा तरिया, आय के जरिया' के तहत प्रदेश में 500 नए तरिया (तालाब) के निर्माण का भी शिलान्यास किया। इससे जल संचयन, भूजल स्तर में वृद्धि और कृषि कार्यों के लिए सिंचाई सुविधा में सुधार होगा। इस अभियान के माध्यम से जल संरक्षण, जल संवर्धन और ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने की दिशा में बड़े स्तर पर कार्य किए जाएंगे।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत इस महाअभियान के तहत प्रदेशभर में 10,000 आजीविका डबरी निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरुद्ध 15 अप्रैल 2026 तक 13,000 से अधिक डबरी निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। यह उपलब्धि अभियान की गति और प्रभावशीलता को दर्शाती है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा कि जल ही जीवन और विकास का आधार है। 'मोर गांव, मोर पानी, मोर तरिया' अभियान के माध्यम से हम गांव-गांव में जल संरक्षण को जन आंदोलन बना रहे हैं। इससे न केवल पानी की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि किसानों की आय में वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

उन्होंने कहा कि आजीविका डबरी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य पालन, बत्तख पालन, सिंघाड़ा उत्पादन, सब्जी उत्पादन और वृक्षारोपण जैसे विविध आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे लोगों को अतिरिक्त आय के अवसर प्राप्त होंगे। ग्रामीण स्तर पर इस योजना के प्रचार-प्रसार के लिए दीवार लेखन, बैनर, ग्राम सभाओं में जागरूकता अभियान तथा क्यूआर कोड के माध्यम से विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी व्यापक प्रचार किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए आजीविका डबरी से जुड़े कार्यों में स्व सहायता समूह की महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। हितग्राही परिवार की महिला सदस्य का नाम नागरिक सूचना पटल में अंकित किया जा रहा है, जिससे महिलाओं की अधिकारिता और भागीदारी मजबूत हो सके।

इसके तहत उन्नत तकनीक आधारित योजना निर्माण और ग्राम सभा की स्वीकृति के आधार पर कार्यों को मंजूरी दी जा रही है, जिससे पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित हो रही है। सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से यह अभियान ग्राम पंचायतों के समग्र विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने का कार्य करेगा। 'मोर गांव, मोर पानी, मोर तरिया' महाअभियान जशपुर सहित पूरे प्रदेश में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाते हुए ग्रामीणों के जीवन में स्थायी बदलाव लाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के रूप में उभर रहा है।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, अध्यक्ष छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल रामप्रताप सिंह, विधायक पत्थलगांव श्रीमती गोमती साय, जशपुर विधायक श्रीमती रायमुनी भगत सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने सियानगुड़ी का किया शुभारंभ, बुजुर्गों के साथ खेला कैरम

श्रीकंचनपथ समाचार

जशपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज जशपुर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विकसित अत्याधुनिक डे-केयर केंद्र 'सियान गुड़ी' का लोकार्पण किया। उन्होंने बुजुर्गों के साथ कैरम खेलकर उनका उत्साह बढ़ाया और संवाद किया। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर वरिष्ठजन भी अत्यंत प्रसन्न नजर आए तथा 'सियान गुड़ी' के लिए आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर बुजुर्गों को फूड बास्केट वितरित किए तथा धार्मिक पुस्तक, शॉल एवं श्रीफल भेंटकर उनका सम्मान किया। उन्होंने वरिष्ठजनों के सम्मान और उनकी देखभाल के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बुजुर्गों की चुनौतियों के समाधान के लिए 'डे-केयर सेंटर - सियान गुड़ी' की परिकल्पना की गई है। यह भवन वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान, आत्मीयता और सक्रियता का एक सशक्त केंद्र बनेगा, जहां वे सुरक्षित वातावरण में दिन व्यतीत कर नई ऊर्जा और उत्साह प्राप्त कर सकेंगे।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सियान गुड़ी' के माध्यम से राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को अधिक सम्मानजनक, सक्रिय और खुशहाल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जो सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करते हुए पारिवारिक मूल्यों को भी नई ऊर्जा प्रदान करेगा। रणजीता स्टेडियम के पीछे भागलपुर रोड स्थित यह 'सियान गुड़ी' वरिष्ठ नागरिकों को राहत देगा।

प्रदेश के विकास में बंगाली समाज की अहम भूमिका, मुख्यमंत्री ने दी बंगाली नववर्ष की बधाई

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय बंगाली समाज के नववर्ष मिलन समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने बंगाली नववर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में बंगाली समाज का सदैव महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विशेष रूप से मत्स्य पालन एवं उन्नत कृषि के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में बंगाली समाज की बड़ी भूमिका रही है। साथ ही, स्वास्थ्य सेवाओं में भी समाज के लोग उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल की भूमि महान विभूतियों की जन्मस्थली रही है, जहां रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया। स्वामी विवेकानंद लंबे समय तक रायपुर में रहे। उनके निवास को विरासत के रूप में संरक्षित किया जा रहा है। उनके सम्मान में विमानतल एवं तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा गया है।

डिजिटल क्रिएटर्स दिखाएं बदलते छत्तीसगढ़ की तस्वीर : साय

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में आयोजित डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग में देशभर से आए कंटेंट क्रिएटर्स का स्वागत एवं अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ आस्था, संस्कृति और प्रकृति का संगम है। उन्होंने डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स से आग्रह किया कि वे बदलते छत्तीसगढ़ की तस्वीर भी दिखाएं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह भूमि भगवान श्रीराम के ननिहाल और माता कौशल्या के मायके के रूप में जानी जाती है। वनवास के अधिकांश समय भगवान श्रीराम ने यहीं व्यतीत किया, जिसके प्रमाण आज भी प्रदेश के विभिन्न स्थलों पर मिलते हैं। उन्होंने माता शबरी की भक्ति, दंडकारण्य और अबूझमाड़ जैसे ऐतिहासिक-आध्यात्मिक स्थलों का उल्लेख करते हुए छत्तीसगढ़ की गौरवशाली विरासत को रेखांकित किया। उन्होंने संत गुरु घासीदास जी के 'मनखे-मनखे एक समान' के संदेश को दोहराते हुए कहा कि सत्य और अहिंसा की यह परंपरा प्रदेश की आत्मा में समाहित है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि कभी नक्सलवाद से प्रभावित रहा छत्तीसगढ़ आज तेजी से बदल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छाशक्ति, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प और सुरक्षा बलों के अदम्य साहस के परिणामस्वरूप प्रदेश अब नक्सलवाद से मुक्त होने की दिशा में निर्णायक सफलता हासिल कर चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा, बस्तर के जलप्रपात, घने वन, संस्कृति और जनजातीय जीवन देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। यूनेस्को द्वारा बस्तर के धुड़मारास गांव को विश्व के 20 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों में शामिल किया जाना प्रदेश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कंटेंट क्रिएटर्स से आग्रह किया कि वे अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए बस्तर और छत्तीसगढ़ की सकारात्मक छवि देश-दुनिया तक पहुंचाएं।

2426 किमी सड़क निर्माण का मुख्यमंत्री ने किया शिलान्यास, 781 बसाहटों तक पहुंचेंगी पक्की सड़कें

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज जशपुर स्थित रणजीता स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (फेज-04) के अंतर्गत स्वीकृत 774 सड़कों का शिलान्यास एवं शुभारंभ किया। इन सड़कों की कुल लंबाई 2426.875 किलोमीटर है, जिनके निर्माण पर 2225.44 करोड़ की लागत आएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिला मुख्यालय स्थित वशिष्ठ कम्यूनिटी हॉल के जीर्णोद्धार के लिए 80 लाख की राशि प्रदान करने की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत एक साथ इतनी बड़ी संख्या में सड़कों का भूमिपूजन ग्रामीण विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि इन सड़कों के निर्माण से लगभग 781 बसाहटों को बारहमासी पक्की सड़क सुविधा प्राप्त होगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी, जो उनकी दूरदर्शी सोच का परिणाम है और आज यह योजना ग्रामीण भारत की जीवनरेखा बन चुकी है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में सड़क नेटवर्क के विस्तार में अभूतपूर्व तेजी आई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन योजना के माध्यम से राज्य के अधिकांश गांवों को सड़क संपर्क से जोड़ा जा चुका है। उन्होंने कहा कि भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर से विशाखापट्टनम तथा रायपुर से जशपुर होते हुए धनबाद तक सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिससे जशपुर क्षेत्र की कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने सहकारिता क्षेत्र का उल्लेख करते हुए बताया कि हाल ही में 515 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) का वर्चुअल शुभारंभ किया गया है, जिससे प्रदेश में समितियों की संख्या बढ़कर 2573 हो गई है। ये समितियां किसानों को खाद, बीज और अल्पकालीन ऋण जैसी सुविधाएं उनके निकट उपलब्ध कराएंगी तथा धान विक्रय प्रक्रिया को सरल बनाएंगी।

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि आज जिन 774 सड़कों का शिलान्यास किया गया है, उनका निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में प्रदेश में 1300 से अधिक सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पीएम जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों में भी सड़क निर्माण तेजी से किया जा रहा है, जिससे ये क्षेत्र भी मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि राज्य में धर्म स्वातंर्त्य कानून लागू कर अवैध धर्मांतरण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं।

'स्पेस ऑन व्हील्स' बना जशपुर के बच्चों के लिए अंतरिक्ष ज्ञान का चलता-फिरता विद्यालय, साय ने किया अवलोकन

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति जिज्ञासा और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जशपुर जिले में 'स्पेस ऑन व्हील्स' कार्यक्रम ने बच्चों में नई ऊर्जा का संचार किया है। रणजीता स्टेडियम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की विशेष मोबाइल प्रदर्शनी बस के आगमन पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंतरिक्ष गाड़ी का अवलोकन किया और प्रदर्शित रॉकेट, उपग्रह तथा विभिन्न अंतरिक्ष मिशनों के मॉडलों को देखा। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद करते हुए उनकी वैज्ञानिक समझ और जिज्ञासा की सराहना की।

शासकीय महारानी लक्ष्मी बाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जशपुर की कक्षा 12वीं की छात्राएं कुमारी अंशु पासवान, भूमिका डाहरे और सारिका साहनी ने आगे बढ़कर चंद्रयान, मंगलयान सहित विभिन्न अंतरिक्ष तकनीकों की कार्यप्रणाली को सरल और प्रभावी ढंग से मुख्यमंत्री को समझाया। बच्चों के आत्मविश्वास से प्रभावित मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी पहलें विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में विज्ञान और तकनीक ही विकास की आधारशिला है और 'स्पेस ऑन व्हील्स' जैसे कार्यक्रम ग्रामीण अंचलों के बच्चों में जिज्ञासा, नवाचार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मजबूत करते हैं।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पेस ऑन व्हील्स के माध्यम से जिले के विभिन्न स्कूलों में विज्ञान की जानकारी देने वाले 17 बच्चों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया और विद्यार्थियों को 'द मैजिक ऑफ नाइट स्काई' पुस्तिका भी वितरित की।

इस अवसर पर विधायक पत्थलगांव गोमती साय, जशपुर विधायक रायमुनी भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद भगत, जिला पंचायत उपाध्यक्ष शौर्य प्रताप सिंह जूदेव, नगर पालिका उपाध्यक्ष यश प्रताप सिंह जूदेव, सरगुजा संभाग के कमिश्नर नरेंद्र दुग्गा, पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार झा, कलेक्टर रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाल उमेंद सिंह सहित बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए 'अन्वेषण' के अंतर्गत इस पहल का अंजाम दिया जा रहा है।

भारत की जनगणना 2027 CENSUS OF INDIA

गृह मंत्रालय भारत सरकार

हमारी जनगणना हमारा विकास

(जनगणना 2027 का पहला चरण)
स्व-गणना (Self Enumeration) से जुड़े सामान्य प्रश्न और उत्तर (भाग-2)

स्व-गणना क्या है?
स्व-गणना एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें आप प्रगणक की प्रतीक्षा किए बिना, स्वयं SE पोर्टल (se.census.gov.in) पर अपने परिवार की जानकारी भर सकते हैं

स्व-गणना के क्या लाभ हैं?
- अपनी सुविधा से जानकारी भर सकते हैं
- गोपनीयता सुनिश्चित
- जनगणना प्रक्रिया को तेज़ और कुशल बनाती है

स्व-गणना पोर्टल में लॉग-इन कैसे करें?
- राज्य / संघ राज्य क्षेत्र चुनें
- मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल (वैकल्पिक) भरें
- OTP द्वारा सत्यापन करें
- स्व-गणना शुरू करें

अपने घर का सही स्थान कैसे चिन्हित करें?
- जिला / पिनकोड चुनें
- क्षेत्र / लैंडमार्क दर्ज करें
- मैप पर ज़ूम करें और घर के पास लोकेशन मार्क करें (सटीक पता न दिखने पर घबराएं नहीं)
- सही लोकेशन चिन्हित करना आवश्यक है

क्या मैं अपनी जानकारी बाद में संशोधित कर सकता / सकती हूँ?
- सबमिट करने से पहले एडिट कर सकते हैं
- सबमिशन के बाद, प्रगणक के आने पर ही बदलाव संभव होगा

क्या स्व-गणना (SE) पोर्टल को भारत के बाहर से एक्सेस किया जा सकता है?
नहीं, यह सुविधा केवल भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर उपलब्ध है

यदि सबमिशन के बाद गलती पता चले तो क्या करें?
प्रगणक के आने पर SE ID के साथ सुधार करवाया जा सकता है

क्या मैं फॉर्म सेव करके बाद में पूरा कर सकता / सकती हूँ?
हां, आप प्रोग्रेस सेव कर सकते हैं और निर्धारित समय के भीतर फॉर्म पूरा कर सकते हैं

टोल फ्री - 1855

चलो निभाएं अपनी ज़िम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी CensusIndia2027

CBC 19108/13/0039/2627

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950